राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

# गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 275 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली,बुधवार ,07 अप्रैल 2021, मूल्य रु. 1.50

## एक नज़र...

### न्यायमूर्ति रमण होंगे अगले प्रधान न्यायाधीश

**नई दिल्ली।** न्यायमूर्ति नूतलपति वेंकट रमण को मंगलवार को भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, न्यायमूर्ति रमण 24 अप्रैल को भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर प्रभार संभालेंगे और मौजूदा सीजेआई एस ए बोबडे की जगह लेंगे। न्यायमूर्ति बोबडे 23 अप्रैल को यह पद छोड़ेंगे। न्यायमूर्ति रमण 26 अगस्त, 2022 को सेवानिवृत्त होंगे।

### न्यायाधीश से फोन पर अनुचित टिप्पणियां करने के मामले में कोलकाता में एक व्यक्ति गिरफ्तार

**कोलकाता।** न्यायाधीश से फोन पर अनुचित बातें कहने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि न्यायाधीश को एक 'ऐप' के जरिए कुछ महीने पहले फोन आया था। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश की शिकायत के आधार पर शनिवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी व्यक्ति की पहचान केन्द्रीय सरकार के एक कर्मचारी के बेटे के तौर पर हुई है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, '' आरोपी ने न्यायाधीश को फोन करने के लिए एक 'ऐप' का इस्तेमाल किया था और अनुचित टिप्पणियां की थीं। हम उससे पूछताछ कर रहे हैं।''

### दिल्ली में निर्माणाधीन पुल की बीम के चार ट्रकों पर गिर जाने से 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत

**नयी दिल्ली।** दिल्ली में एक निर्माणाधीन पुल के दो खंभों के बीच सहारा देने के लिए लगाई गई सीमेंट और लोहे की बीम पास खड़े चार ट्रकों पर गिर गई, जिससे 50 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) प्रशांत गौतम ने मंगलवार को बताया कि सोमवार की रात पश्चिम दिल्ली के पंजाबी बाग में राम बहादुर एक ट्रक में सो रहा था, तभी यह हादसा होने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि अशोक पार्क में रहने वाला बहादुर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का मूल निवासी था और वह खड़े किए जाने वाले ट्रकों की रात में चौकीदारी करता था। दमकल विभाग ने बताया कि उसे मंगलवार को सुबह आठ बजकर 48 मिनट पर फोन पर इस हादसे की सूचना मिली और दमकल की दो गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं। पुलिस और केंद्रीकृत दुर्घटना आघात सेवा (सीएटी) एम्बुलेंस के साथ आपदा प्रबंधन दल घटनास्थल पर पहुंचा और शव को मलबे से बाहर निकाला गया।

### प्रतिबंधों पर गोवा के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की जाएगी: विश्वजीत राणे

**पणजी।** गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए राज्य में कुछ प्रतिबंध लगाने की संभावना पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से चर्चा की जाएगी। सावंत ने सोमवार को कहा था कि गोवा में लॉकडाउन या कर्फ्यू लागू करने की तत्काल कोई योजना नहीं है, लेकिन उनकी सरकार गोवा और पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में कोविड-19 के हालात पर नजर रख रही है। राणे ने तटवर्ती राज्य में कोविड-19 संबंधी हालात की समीक्षा के लिए सोमवार को स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और बाद में मुख्यमंत्री से मुलाकात की।बैठक में कोविड-19 केंद्रों में बिस्तरों के जल्द भरने की बात पर चिंता व्यक्त की गई। राणे ने कहा, ''मैंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें जमीनी हालात के बारे में बताया। मैं महामारी से निपटने की भावी रणनीति पर फैसला करने के लिए आज दोबारा उनसे मुलाकात करूंगा।''

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में कुछ प्रतिबंध लागू करने पर चर्चा की जाएगी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गोवा में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 247 नए मामले सामने आए और इसी के साथ राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 59,315 हो गए हैं।

## बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं बल्कि दिल जीतने का अभियान,पार्टी के स्थापना दिवस पर बोले मोदी

**नई दिल्ली ।** प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी ने मंगलवार को कहा कि भाजपा चुनाव जीतने की मशीन नहीं बल्कि देशवासियों का दिल जीतने वाला अविरल व अनवरत अभियान है और भाजपा की सरकारों का मतलब राष्ट्र निर्माण, सही नीति, साफ नीयत और सटीक निर्णय है. भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भाजपा का मतलब परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति और सुशासन है. केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पहले सरकारों के प्रदर्शन का मानदंड उसकी घोषणाओं से होता था लेकिन पिछले कुछ सालों में यह अवधारणा बदली है और अब सरकारों का मूल्यांकन केंद्र की योजनाओं का जमीन तक पहुंचने से हो रहा है.

उन्होंने कहा, ''आखिरी पायदान पर खड़े इंसान तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना और हकदार तक उसका हक पहुंचाना हमारी सरकार की विशेषता रही है। यह भाजपा सरकारों के कामकाज का मूल मंत्र रहा है. मोदी ने कहा कि इसके बावजूद भाजपा जब चुनाव जीतती है तो उसे चुनाव जीतने की मशीन कहा जाता है जबकि दूसरे जीतते हैं तो पार्टी और उसके नेताओं की वाहवाही की जाती है. उन्होंने कहा, ''इस तरह के दो मापदंड हम देख रहे हैं. जो लोग कहते हैं कि भाजपा चुनाव जीतने की मशीन है, वह एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता, भारत के नागरिकों की सूझबूझ का आकलन ही नहीं कर पाते हैं. उन्होंने कहा, ''सच्चाई यह है कि भाजपा चुनाव जीतने की मशीन नहीं, देश और देशवासियों का दिल जीतने वाला अविरल, अनवरत अभियान है। हम पांच साल तक ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं। हर परिस्थिति में हम जनता से जुड़े रहते हैं. जनता के लिए जीते रहते हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकारों का मतलब राष्ट्र निर्माण के लिए सही नीति, साफ नीयत और सटीक निर्णय है. उन्होंने कहा, ''भाजपा की सरकार का मतलब है राष्ट्र प्रथम। देशहित से समझौता नहीं बल्कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि. भाजपा का मतलब है वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति, भाजपा का मतलब है योग्यता को अवसर, पारदर्शिता और सुशासन। भाजपा का मतलब है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास.

मोदी ने कहा कि आज भाजपा भारत की विविधता में एकता और अनेकता में एकता की प्रतीक बन गई है. उन्होंने कहा, ''हम हर भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय और सभी देशवासियों को जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं. आज भाजपा से गरीब भी जुड़ा है, मध्यमवर्ग भी हमारे साथ है. हम शहर में भी हैं और गांव में भी हैं. भाजपा आज राष्ट्रीय हित की भी पार्टी है और क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी पार्टी है.

## अब भी अनिल देशमुख के बचाव में उद्धव सरकार

*सीबीआई जांच के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती*

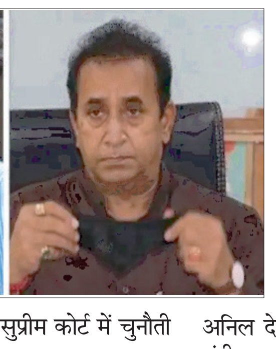

**नई दिल्ली ।** महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के फैसले को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है, इसमें सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है. देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दाखिल की है. राज्य सरकार ने याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी करेंगे. महाराष्ट्र सरकार के अलावा अनिल देशमुख ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था. बता दें कि परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी. परमबीर के आरोपों के अनुसार, देशमुख ने कई पुलिस अधिकारियों को हर माह 100 करोड़ रुपये की वसूली का निर्देश दे रखा था. उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया था और बाद में नैतिक आधार पर अनिल देशमुख को महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.

इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने परमबीर सिंह को फटकार लगाते हुए पूछा था कि अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज गई. कोर्ट ने सिंह से कहा आप जैसा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तक कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तब तक सीबीआईजांच का आदेश कैसे दिया जा सकता है?

### राहुल ने राफेल सौदे से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट को लेकर सरकार पर निशाना साधा

## 'कर्म का फल तो मिलता है'

**नई दिल्ली, (वेबवार्ता)।** कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल सौदे में एक बिचौलिये को 11 लाख यूरो (करीब 9.5 करोड़ रुपये) का भुगतान किए जाने के दावे संबंधी फ्रांसीसी मीडिया की एक खबर को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल सामने आ जाता है तथा इससे कोई बच नहीं सकता। उन्होंने ट्वीट किया, ''कर्म किसी के कार्यों का लेखाजोखा। कोई इससे बच नहीं सकता।'' उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी समाचार पोर्टल 'मीडिया पार्ट' ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि फ्रांसीसी भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी (एएफए) ने खुलासा किया है कि राफेल की निर्माता कंपनी दसॉल्ट ने एक बिचौलिये को 11 लाख यूरो का कथित तौर पर भुगतान किया था। कांग्रेस ने इस खबर का का हवाला देते हुए सोमवार को इस मामले में निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी तो भाजपा ने आरोपों को 'पूरी तरह निराधार' करार देते हुए आरोप लगाया था कि मुख्य विपक्षी पार्टी सुरक्षा बलों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला संवाददाताओं से कहा कि फ्रांस के एक समाचार पोर्टल ने अपने नये खुलासे से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इस रुख को सही साबित किया है कि राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है।

**कर्म- किये कराये का बही खाता..**

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में भगवद्गीता और रामचरित मानस की तर्ज पर 'कर्म' का उल्लेख करते हुए आज राफेल लड़ाकू विमान सौदे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और कहा कि जो कर्म करोगे उसका फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। राफेल लड़ाकू विमान सौदे में फ्रांस के एक मीडिया संस्थान के भारत के एक बिचौलिया को रिश्वत देने के मामले का खुलासा होने के बाद कांग्रेस सरकार पर आक्रामक हो गयी है और पार्टी ने इस संबंध में सोमवार को विशेष प्रेस कांफ्रेंस कर श्री मोदी से देश की जनता को स्पष्टीकरण देने और असलियत बताकर इस पूरे प्रकरण की व्यापक जांच कराने की मांग की थी। राहुल गांधी ने राफेल प्रकरण में हुए इस नये खुलासे को लेकर सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया कर्म- किये कराये का बही खाता। इससे कोई नहीं बच सकता।

### कांग्रेस के दावे पर बीजेपी का पलटवार

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से कहा कि फ्रांस के एक समाचार पोर्टल ने अपने नए खुलासे से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस रुख को सही साबित किया है कि राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है. इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ BJP नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये आरोप पूरी तरह गलत हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की जांच कराने संबंधी मांग को खारिज कर दिया था और साथ ही, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने इसमें कुछ गलत नहीं पाया था.

## पूरे देश मे लग जाए लॉकडाउन, आंदोलन नहीं होगा खत्म -टिकैत

"भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि, इसको शाहीन बाग मत बनाने दो उन लोगों को। पूरे देश मे लॉकडाउन लग जाए लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। जो भी कोरोना गाइडलाइंस होंगी उसका पालन आंदोलन स्थलों पर किया जाएगा।

**नई दिल्ली, (वेबवार्ता)।** देशभर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हालात फिर बिगड़ते गए हैं। कोरोना के कारण हर तरफ खतरा बढ़ गया है। ऐसे में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे सैंकड़ो की संख्या में किसानों पर भी कोरोना का सीधा खतरा बना हुआ है। लेकिन किसान इस आंदोलन को न खत्म करने की बात दोहरा रहे हैं। बीते कुछ समय से कोरोना ने ऐसी स्पीड पकड़ी कि सात-आठ महीने का रिकॉर्ड टूट गया हैं। देश में पहली बार अब एक दिन में एक लाख से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। लेकिन कृषि कानून के खिलाफ हो रहे विरोध में किसान ऐसे खतरा होने के बावजूद हटने का विचार नहीं कर रहें हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस मसले पर बात करते हुए कहा कि, इसको शाहीन बाग मत बनाने दो उन लोगों को। पूरे देश मे लॉकडाउन लग जाए लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। जो भी कोरोना गाइडलाइंस होंगी उसका पालन आंदोलन स्थलों पर किया जाएगा। हालांकि बॉर्डर पर किसान कोरोना नियमो की साफ अनदेखी भी कर रहें हैं। किसान ना तो मुंहँ पर मास्क और न ही सेनिटाइजर इस्तेमाल करते नजर आते हैं। जिससे कोरोना का खतरा किसानों पर ज्यादा बढ़ जाता है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को 3,548 नए मामले दर्ज होने के बाद कुल मामले 6,79,962 हो गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट 5.54 प्रतिशत है। यह लगातार चौथा दिन है कि जब दिल्ली में 3,500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले रविवार को यहां 4,033 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो कि साल 2021 का सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा था।

## महाराष्ट्र में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट का 24 फीसद होना चिंताजनक : स्वास्थ्य मंत्रालय

**नई दिल्ली, एजेंसी।** देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में कुल कोविड मामलों में से 92 फीसद मरीज रिकवर हो चुके हैं। 1.3 फीसद मौतें हुई हैं। लगभग 6 फीसद नए कोविड मामले हैं। महाराष्ट्र में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट फरवरी में 6 फीसद हो गई थी। अब यह 24 फीसद हो गई है, जो चिंता का विषय है। सबसे अधिक कोरोना के मामले वाले जिलों में 7 महाराष्ट्र के हैं। देश के कुल मामलों में से लगभग 58 फीसद मामले महाराष्ट्र में आ रहे हैं। कोविड से मृत्यु के मामलों के लगभग 34 फीसद महाराष्ट्र में दर्ज किए जा रहे हैं। जो लोग इन्फेक्टेड हैं या आइसोलेटेड हैं, वहां पर कड़ाई की जरूरत, अभी छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। छोटा राज्य होने के बावजूद कोरोना के कुल 6 प्रतिशत मामले छत्तीसगढ़ से आए हैं और मौतों का कुल 3 प्रतिशत छत्तीसगढ़ से है। कोरोना की दूसरी लहर की शुरूआत से ही छत्तीसगढ़ में न केवल इंफेक्शन ज्यादा आए हैं बल्कि मौतें भी ज्यादा हुई हैं! छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन होने वाली मौतों के आंकड़े 38 दर्ज की गई हैं, और औसत केस 4900 से अधिक दर्ज की गई है।

हमारा मकसद किसी राज्य पर उंगली उठाना नहीं है, ये एक मिलजुलकर काम करने की एक्सरसाइज है, जिसमें भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिल कर काम कर रही है, इसलिए हम छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आस पास बड़ी आबादी वाले राज्यों में न केवल औसत केस कम हैं, साथ ही मौतें भी कम हुई हैं। अब आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने का अनुरोध राज्य सरकार से किया गया है।

देश भर में कोरोना के 3 प्रतिशत केस पंजाब से आ रहे हैं, देश में कोरोना से होने वाली कुल मौतों का 4 प्रतिशत आंकड़ा पंजाब से आ रहा हैं। एक्टिव केस और मौतों के आंकड़ों के मामले में दिल्ली और हरियाणा की स्थिति पंजाब से बहुत बेहतर है।

पंजाब में आरटीपीसीआर का शेयर 76 प्रतिशत है जो काफी हद तक संतेषजनक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे सुधारने की जरूरत है। कर्नाटक में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं, पहले 399 केस हुआ करते थे जो अब बढ़ कर 4376 हो गए हैं। मामलों में 4 गुना इज़ाफा परेशानी का सबब है। सोमवार को देश में वैक्सीन के 43 लाख डोज लगाए गए जिसके चलते हमने आज सुबह तक 8 करोड़ 31 लाख डोज लगाए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 96,982 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1 कोरड़ 26 लाख 86 हजार 49 हो गई है। इस दौरान हुई 446 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1 लाख 65 हजार के पार हो गई है।

देश में लगातार 27 दिनों से नए मामलों में हो रही बढ़ोतरी के बाद सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़कर 7 लाख 88 हजार 223 हो गई, जो कुल मामलों का 6.21 फीसद है।

## दिल्ली में भी लगा नाइट कर्फ़्यू

### रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी; बहुत तेजी से बढ़ रहा संक्रमण

नई दिल्ली, (वेबवार्ता)। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज मंगलवार से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ़्यू लागू कर दिया है। ये कर्फ़्यू 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,548 नए मामले सामने आए हैं जबकि 15 लोगों ने इस महामारी से अपनी जानें गंवाई है। अभी राजधानी में 14 हजार से अधिक एक्टिव केस हैं। चार अप्रैल को राजधानी में चार हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए थे जबकि पूरे देश में पूरे कोरोना काल में सर्वाधिक एक लाख से अधिक मामलों की पुष्टि हुई थी। तेज वैक्सीनेशन प्रक्रिया के बीच देश में कोरोना के मामलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। चार अप्रैल को महाराष्ट्र में 57हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। महाराष्ट्र की स्थिति सबसे भयावह है। राज्य सरकार ने बीते दिनों बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में शुक्रवार की रात आठ बजे से सोमवार की सुबह आठ बजे तक फुल शटडाउन का फैसला किया है। नाइट कर्फ़्यू पूरे राज्य में लगाया जा चुका है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार इस बीच देश में 96,982 नये मामले दर्ज किए गए। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या एक करोड़ 26 लाख 86 हजार 049 हो गयी है। वहीं इस दौरान 50,143 मरीज स्वस्थ हुए हैं जिसे मिलाकर अब तक 1,17,32,279 मरीज कोरोनामुक्त भी हो चुके हैं। सक्रिय मामले 46,393 बढ़कर 7,88,223 हो गये हैं। इसी अवधि

### 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को भी टीका लगवाए केन्द्र सरकार: आईएमए

देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाने की गुहार लगाई है। आईएमए ने मंगलवार को इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में टीकाककरण कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर करने की सलाह दी है। आईएमए ने अपने सुझाव में कहा है कि टीकाकरण की गति को तेज करते हुए 18 साल के ऊपर के सभी लोगों के लिए टीका लगाने की शुरुआत करनी चाहिए।

## भारत में एक दिन में सर्वाधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए

**नयी दिल्ली, (वेबवार्ता)।** देश में पिछले 24 घंटों में 43 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 रोधी टीका लगाया गया जो अब तक एक दिन में दी गई खुराकों के लिहाज से सर्वाधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार तक के आंकड़ों के मुताबिक अब तक टीकों की कुल 8,31,10,926 खुराक दी जा चुकी हैं। मंत्रालय के सुबह सात बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक टीकाकरण अभियान के 80वें दिन टीके की कुल 43,00,966 खुराकें दी गईं जिनमें से 39,00,505 लाभार्थियों को पहली खुराक जबकि 4,00,461 लाभार्थियों को दूसरी खुराक दी गई।

मंत्रालय ने कहा, ÷यह देश में अब तक एक दिन में दिए गए टीकों के लिहाज से सर्वाधिक है। इसने कहा, एक अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम में, देश में कोविड-19 रोधी टीके की कुल संख्या 8.31 के आंकड़े को पार कर गई है। पहली खुराक का आंकड़ा भी सात करोड़ (7,22,77,309) का आंकड़ा पार कर गया है। सुबह सात बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के मुताबिक 12,83,816 सत्रों के माध्यम से 8,31,10,926 टीके दिए गए। इनमें 89,60,061 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं जिन्हें पहली खुराक दी गई और 53,71,162 ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्हें दूसरी खुराक दी गई।

## देश में फैला है माफिया, कारोबार पर है बुकीज का राज, इनका अब बच पाना मुश्किल : इमरान खान

**इस्लामाबाद।** पाकिस्तान में महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच गई है। सरकार से लेकर आम आदमी तक हर कोई इससे परेशान है। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सभी से अपील की है कि वो इससे एकजुट होकर लड़ें। इसके लिए उन्होंने देश में फैले भ्रष्टाचार रोकने, लोगों पर भारी पड़ रही महंगाई दर को कम करने और कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए देश की जनता से मदद मांगी है। इसके अलावा उन्होंने देश में बढ़ते बेहूदापन को रोकने में भी लोगों की मदद मांगी है। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि वह कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेंगे जो देश के हितों के खिलाफ हो, इसमें भारत से व्यापार और आईएमएफ कंडीशन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वो अकेले इन सभी समस्याओं से नहीं निपट सकते हैं। इसलिए उन्हें इसमें देश की जनता का साथ चाहिए। उन्होंने टेलिथॉन के तीसरी पब्लिक इंटरैक्शन के दौरान कही।

पाकिस्तान के खबर के मुताबिक, पाक पीएम ने कहा कि बदलाव कभी भी रातों रात नहीं आता है। आर्थिक स्थिरता लाने के लिए विकास के लिए वर्षों की मेहनत और इंतजार करना होता है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को इमरान खान से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो आएगा और देश को बदल कर रख देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा सिर्फ कहानियों में ही होता है। इमरान खान ने कहा कि दो तरह की क्रांति होती हैं। एक खूनी और दूसरी बैलेट से होती है। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी बैलेट के जरिए देश की सत्ता पर काबिज हुई है। इसलिए बदलाव लाने में उसको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर देश के धन को लूटने वालों को कोर्ट सुरक्षा प्रदान करती है और वो करोड़ों रुपये स्विस बैंक में रखते हैं। एक महिला के महंगाई के बाबत सवाल किए जाने पर इमरान खान ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति लगातार सुधर रही है। इसलिए देश की जनता को डरना नहीं चाहिए। सरकार जल्द ही बढ़ती कीमतों को काबू में कर लेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने जरूरी चीजों की कीमतों पर चेक लगाया है। लाहौर में इसकी शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही ये देश के दूसरे शहरों में भी शुरू हो जाएगा। पहली बार देश की अर्थव्यवस्था स्थिर है और रुपया भी मजबूत हो रहा है। रुपये और डॉलर की कीमत में आई दूरी का असर पावर जनरेशन पर पड़ा है। डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और इसकी वजह से दूसरी चीजों की कीमतों पर भी फर्क आया है।

## पीएम मोदी की ढाका यात्रा का विरोध करने वालों पर बरसीं शेख हसीना, कहा- आग से खेल रहे हैं हिफाजत-ए-इस्लाम के आतंकी

**ढाका।** बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सोमवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाका यात्रा का विरोध करने वालों पर जमकर बरसीं। उन्होंने हिफाजत-ए-इस्लाम के आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे आग से खेल रहे हैं और अगर बाज नहीं आए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हसीना ने जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार उग्रवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस्लाम के नाम पर किसी पर हमला करना ठीक नहीं है। संसद में बोलते हुए शेख हसीना ने कहा, क्या हिफाजत-ए-इस्लाम से जुड़े लोग भारत स्थित देवबंद पढ़ने नहीं जाते हैं। अगर ऐसा है तो आपको भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा का विरोध करने का अधिकार किसने दिया।

आप जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो सरकार सारा इंतजाम करती है, लेकिन इसके बावजूद विरोध करना आश्चर्यचकित करता है। शेख हसीना ने हिफाजत-ए-इस्लाम के नेताओं की नैतिकता और ईमानदारी पर भी सवाल उठाया। प्रमुख रूप से उनका निशाना संयुक्त महासचिव मामूनुल हक पर था। हसीना ने हक की आमदनी के स्रोत को लेकर भी सवाल खड़ा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का आम आदमी इस्लाम को नष्ट करने वाले ऐसे आतंकियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। शेख हसीना ने सवाल करते हुए कहा कि इस्लाम शांति का धर्म है, लेकिन इसके बावजूद इन आतंकियों ने जनता पर हमला किया।

## अपनी हिमाकत से बाज नहीं आ रहा चीन, एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में गतिरोध जारी

**हांगकांग।** चीनी मिलिशिया के नावों की मौजूदगी से दक्षिण चीन सागर में गतिरोध शुरू हो गया है। दरअसल यूनियन बैंक व व्हिटसन रीफ जहां मार्च की शुरुआत में 220 चीनी नाव मौजूद थे वह फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र के 220 नॉटिकल मील के भीतर थे। यदि फिलीपींस प्रतिक्रिया नहीं देता है तब यह यूनियन बैंक के इस जगहों को अलविदा कर सकता है। इसमें से एक फिलीपींस के अहम थिटू आइलैंड से मात्र 129 किमी की दूरी पर है। जब फिलीपींस ने व्हिटसन रीफ से चीन को हटने के लिए कहा तब उसका जवाब था कि यह उनका अधिकार क्षेत्र है। उस वक्त चीन की इन करतूतों के मद्देनजर फिलीपींस ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में मिलिशिया द्वारा चलाए जा रहे सैकड़ों चीनी जहाज बड़े पैमाने पर फैल गए हैं और अपने जहाजों के बेड़े को इस क्षेत्र से हटाने की फिलीपींस की मांग को ठुकरा दिया। फिलीपींस ने व्हिटसन रीफ में अपने 200 मील के विशेष आर्थिक क्षेत्र में चीनी नावों की मौजूदगी को झुंड और धमकी करार दिया। वहीं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और अन्य देशों ने इस क्षेत्र में की जा रही गतिविधियों को लेकर चीन के इरादे पर संदेह जताया। इसपर चीन ने इन देशों को फटकार लगाई और कहा कि नौकाएं अशांत समुद्र से पनाह ले रही हैं और उनमें कोई मिलिशिया सवार नहीं है।

# पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं

### रूस के राष्ट्रपति ने 6-6 साल के दो टर्म बढ़ाने संबंधी कानून पर साइन किए; 2024 में खत्म हो रहा कार्यकाल

**काबुल।** रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस कानून पर साइन किए, जो उन्हें 2036 तक सत्ता में बने रखने ताकत देता है। इसके साथ ही पुतिन को राष्ट्रपति पद पर अन्य दो कार्यकाल तक बने रहने की मंजूरी मिल गई है। 68 साल के पुतिन पिछले दो दशक से ज्यादा समय से रूस की सत्ता में हैं। सरकार के लीगल इंफॉरमेशन पोर्टल पर जारी की गई एक कॉपी के मुताबिक, पुतिन के हस्ताक्षर के बाद अब वह 2024 में वर्तमान कार्यकाल पूरा होने के बाद अगले चुनावों में भी खड़े हो सकेंगे।

**76फीसदी लोगों ने समर्थन किया था**

पिछले साल रूस में संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह अभियान भी चलाया गया था। यह 7 दिन तक चला था। कोरोना संकट के कारण पहली बार रूस में किसी वोटिंग में इतना वक्त लगा। हालांकि, वोटिंग ऑनलाइन हुई। करीब 60त्न वोटरों ने मतदान किया। रूस की जनता ने पुतिन को 2036 तक पद पर बनाए रखने के समर्थन और विरोध में वोट दिए थे। इसके मुताबिक 76त्न लोगों ने संविधान में संशोधन का समर्थन किया था।

**पुतिन पहली बार 2000 में राष्ट्रपति बने थे**

पुतिन पहली बार 7 मई 2000 को राष्ट्रपति बने थे। उनका पिछला कार्यकाल

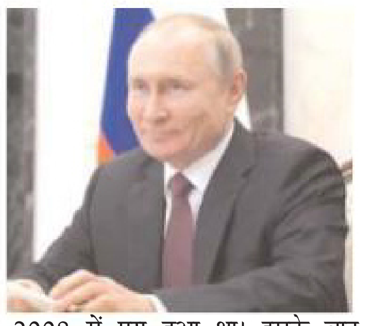

2008 में पूरा हुआ था। इसके बाद मेदवेदेव राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे और पुतिन प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि, सरकार की असल कमान पुतिन के हाथों में थी। मेदवेदेव के राष्ट्रपति रहने के दौरान राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल कर दिया गया था। इससे पहले यह 4 साल का हुआ करता था। 2012 में एक बार फिर से पुतिन राष्ट्रपति बने और मेदवेदेव प्रधानमंत्री चुने गए। इस दौरान देश में कई बदलाव देखने को मिले। इसके साथ ही राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने खुद को बेहद मजबूत बनाया।

**रूसी संसद के निचले सदन में आया था प्रस्ताव**

पुतिन का कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है। अगर संविधान संसोधन नहीं होता, तो पुतिन इस बार चुनाव नहीं लड़ पाते। इसके लिए रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा में पुतिन की टर्म बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव लाया गया था। संसद में यह प्रस्ताव सांसद वेलेंतीना तेरेश्कोवा लाई थीं। वे 1963 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला हैं। वे पुतिन की समर्थक मानी जाती हैं।

**15 साल तक जासूस के रूप में काम किया**

रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के जासूस के रूप में उन्होंने विदेश में 15 साल तक काम किया। जब रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने 1999 में अचानक इस्तीफा दिया, तब पुतिन देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय लंबित चुनावों के बीच उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया।

## कोरोना दुनिया में: वैक्सीन लगवा चुके और संक्रमण से ठीक हो चुके लोग ही मक्का-मदीना जा सकेंगे

### ब्राजील में लगातार दूसरे दिन 40 हजार से कम नए केस

**रियाद।** कोरोना के बीच राहत भरी खबर आ रही है। इस साल रमजान की शुरुआत के साथ ही मक्का की मस्जिद में जायरीनों एंट्री शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब ने फैसला किया है कि यहां उन्हें ही एंट्री दी जाएगी जिन्हें कोरोना की वैक्सीन लग चुकी हो या जो कोरोना से संक्रमित होने के बाद उसे मात दे चुके हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ऐसे लोग जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, उन्हें 14 दिन क्वारैंटाइन रहने के बाद एंट्री दी जाएगी। मदीना में भी ऐसी ही पाबंदियों के साथ एंट्री की इजाजत होगी।

**कोरोना की वजह से नहीं हो सकी थी हज यात्रा**

पिछले साल कोरोना महामारी के कारण दुनियाभर के धार्मिक स्थलों को बंद किया गया था। सऊदी सरकार ने भी पिछले साल 27 फरवरी को उमरा पर बैन लगा दिया था। उमरा हज की तरह ही होता है, लेकिन निश्चित इस्लामी महीने में मक्का और मदीना की यात्रा को हज कहा जाता है। महामारी को रोकने के लिए सरकार ने सभी सीमाएं सील कर दी थीं। दुनियाभर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले

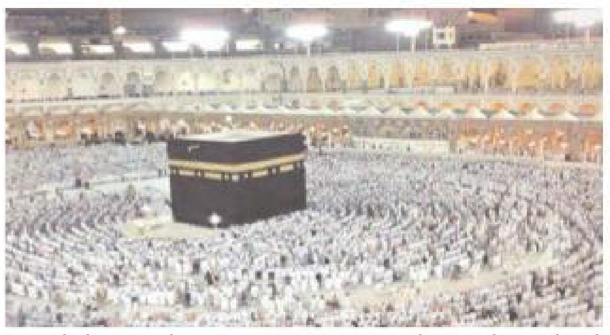

24 घंटे में दुनिया में 4.68 लाख लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 7,255 लोगों की मौत भी हुई।

रोजाना के सबसे ज्यादा केस भारत में मिल रहे हैं। सोमवार को भारत में 96,557 केस आए। इसके बाद अमेरिका में 50,329 और तुर्की में 42,551 मरीज मिले। ब्राजील 38,233 नए मामलों के साथ चौथे नंबर रहा। यहां रविवार को 31,359 मामले सामने आए थे।

**ब्रिटेन में लॉकडाउन में ढील देने की तैयारी**

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अगले हफ्ते से अनलॉक का दूसरा फेज शुरू करने का ऐलान किया। सरकारी डेटा के मुताबिक, देश ने लॉकडाउन की पाबंदियां आसान करने के लिए सभी 4 टेस्ट पूरे कर लिए हैं और पाबंदियों को आगे बढ़ाने की कोई वजह नजर नहीं आती।

जॉनसन के मुताबिक, दूसरे फेज में दुकानें, जिम, जू और पर्सनल केयर सर्विसेज जैसे हेयर ड्रेसर, बीयर गार्डन और सभी तरह की आउटडोर हॉस्पिटैलिटी फिर से शुरू की जाएंगी। जॉनसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपकी कोशिशों और वैक्सीनेशन ड्राइव के नतीजों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि सोमवार, 12 अप्रैल से हम अपने रोडमैप का दूसरा फेज शुरू करेंगे।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि वह 12 अप्रैल को खुद पब जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम घर में आने-जाने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाकर एक से 2 कर रहे हैं, ताकि लोग अपने करीबियों से मिल सकें।

**अब तक 13.24 करोड़ लोग संक्रमित:** दुनिया में अब तक 13.24 करोड़ लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 10.66 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 28.73 लाख मरीजों की मौत हो गई। 2.27 करोड़ मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इनमें 98,332 मरीजों की हालत गंभीर है।

## हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

### सिंगापुर पीएम के खिलाफ पोस्ट लिखने पर 72 लाख रुपए का जुर्माना,ब्लॉगर ने क्राउडफंडिंग से जुटा लिया

हियान ने इस जुर्माने की रकम को जुटाने के लिए क्राउडफंडिंग का सहारा लिया। लिओंग के वकील लिम टीन के मुताबिक, जुर्माने से ज्यादा की रकम जमा हो चुकी है और 2 हजार लोगों ने अभियान में दान दिया है।

**सिंगापुर।** सिंगापुर के एक ब्लॉगर लियोंग सेज हियान पर प्रधानमंत्री ली हसियन लूंग को बदनाम करने पर हाईकोर्ट ने एक लाख डॉलर (लगभग 72 लाख रुपए) का जुर्माना लगाया गया है। हियान ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री का मलेशिया में मनी-लॉन्ड्रिंग घोटाले से संबंध है।

हियान ने इस जुर्माने की रकम को जुटाने के लिए क्राउडफंडिंग का सहारा लिया। लिओंग के वकील लिम टीन के मुताबिक, जुर्माने से ज्यादा की रकम जमा हो चुकी है और 2 हजार लोगों ने अभियान में दान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस अभियान से हर नागरिक को विश्वास हुआ है कि लियोंग उनकी बात को दबाने वालों के खिलाफ कवच बनेंगे। कोर्ट के फैसले पर लियोंग ने कहा, 'मैं निराश हूं। मुझे उम्मीद है कि यह आखिरी बार है जब कोई भी राजनेता आम लोगों पर मानहानि का मुकदमा करेगा।' बता दें कि सिंगापुर के नेताओं ने अक्सर आलोचकों के खिलाफ अदालतों का रुख किया है। उनका मानना है कि प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कार्रवाई आवश्यक है।

विरोध का एक और चेहरा मैदान में उतरा

## म्यांमार में सेना के खिलाफ उतरी 22 साल की ब्यूटी क्वीन, बोलीं- दुनिया हमारी मदद करे

**यांगून।** म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ चल रहा विद्रोह 65वें दिन भी जारी रहा। सेना दमन करने के लिए लोगों को गोलियों से छलनी करती जा रही है। अब तक 550 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद लोग झुक नहीं रहे हैं। विरोध का चेहरा रही 16 साल की लड़की सेना ने मार डाला।

दूसरा चेहरा रहीं नन ने अड़कर कहा कि या तो कत्लेआम बंद करो या मुझे मार दो। अब इस संग्राम का नया चेहरा बनकर उभरी हैं म्यांमार की ब्यूटी क्वीन हैन ले। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शनिवार को मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट आयोजन था। इसमें मिस ग्रैंड म्यांमार, 22

साल की हैन ले ने देश की मदद की अपील की।

ले ने कहा, आज जब मैं इस स्टेज पर हूं, तो मेरे देश म्यांमार में लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। मुझे जान गंवाने वालों के लिए दुख है।' ले बोलते हुए अपने आंसू नहीं पाईं। उन्होंने कहा, हर कोई अपने देश में खुशहाली समृद्धि और शांतिपूर्ण वातावरण चाहता है। पर सत्ता में राज करने के लिए नेताओं को अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्लीज म्यांमार की मदद कीजिए। हमें तत्काल अंतरराष्ट्रीय मदद की जरूरत है।'

## ब्रिटेन में गर्मी शुरू होते ही लौटी सर्दी

### एक दिन पहले गर्मी के कारण बीच पर घूम रहे थे लोग, सुबह उठे तो बर्फबारी ने बढ़ा दी ठंड

**लंदन।** ब्रिटेन में तेज गर्मी शुरू होते ही सर्दी लौट आई है। रात आर्कटिक की ओर से चली बर्फीली हवा ने ठंड तो बढ़ाई ही, साथ ही बर्फबारी भी करा दी। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स काउंटी समेत कई जगहों पर 12 घंटे में तापमान 20 डिग्री तक गिर गया। करीब डेढ़ इंच बर्फबारी हुई। इससे तापमान माइनस तीन डिग्री तक पहुंच गया।

मौसम विभाग ने बताया कि लंदन का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। गर्मी के कारण लोग घूमने के लिए समुद्री किनारों पर पहुंच रहे थे। लेकिन रात में गिरे तापमान के कारण लोग सोमवार सुबह से ही घरों में कैद हैं। मौसम विभाग की

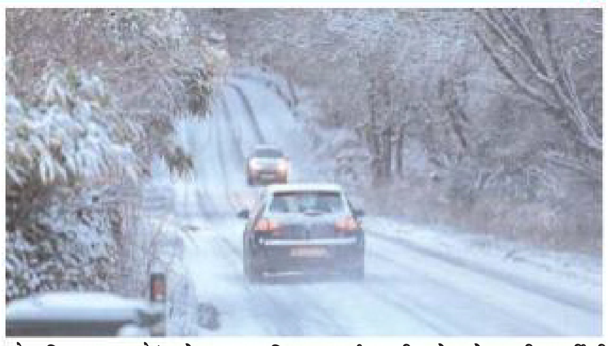

वैज्ञानिक सारा कैंट ने बताया कि आर्कटिक सर्कल की तरफ से 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही है। इसके चलते अगले तीन दिनों में भारी बर्फबारी हो सकती है।

**अमेरिका: 74 साल की रिकॉर्ड बर्फबारी:** आर्कटिक सर्कल की ओर से चली बर्फीली हवा का असर अमेरिका में भी दिखा। वहां के अलास्का प्रांत में पिछले 24 घंटे में 21 इंच बर्फबारी हुई। इसने पिछले 74 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले साल 1948 में अप्रैल में 16 इंच बर्फबारी हुई थी।

## पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की फजीहत:इमरान बोले- बुर्का पहनो, दुष्कर्म से बचो; लोगों ने उनका अर्धनग्न वीडियो शेयर किया

**इस्लामाबाद।** पाकिस्तान में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने में नाकाम पीएम इमरान खान ने महिलाओं को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म से बचना है तो महिलाएं पर्दा करें। बुर्का पहनन से ऐसी घटनाएं थम सकेंगी। उनकी इस सलाह का लोगों का उल्टा असर हुआ और इमरान की फजीहत होने लगी। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनका एक पुराना वीडियो शेयर किया। इसमें इमरान अर्धनग्न हैं और उनके साथ बिकिनी में महिला मौजूद है। दोनों लोग समुद्र में नहाकर निकलते दिखे। लोगों ने कहा- पीएम इमरान पहले अपनी गिरेबां झाक लें।

इमरान ने महिलाओं को ये सलाह तब दी जब वे रेडियो पर जनता से सीधे फोन पर बात कर रहे थे। एक कॉलर ने पूछा- यौन हिंसा खासकर बच्चों से हो रही घटनाओं को लेकर सरकार की क्या योजना है? इसके जवाब में देश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था की बजाय इमरान ने 'फताशी' (अश्लीलता) को जिम्मेदार बताया। उन्होंने दिल्ली को रेप केपिटल तक बता दिया। बता दें कि पाकिस्तान में रोज 11 दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। 6 साल में 22 हजार से ज्यादा केस आए। सिर्फ 0.3 फीसदी लोगों को सजा हुई।

# पाकिस्तान को मुश्किल में डाल देगा लोगों का ये रवैया, सरकार को मजबूर न करे जनता : इमरान खान

**इस्लामाबाद।** पाकिस्तान में लगातार कोविड-19 का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण के अब तक 692231 मामले सामने आ चुके हैं जबकि 21928 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलााव 615960 मरीज ठीक भी हुए हैं। यहां पर एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी संख्या 249841 तक जा पहुंची है जिनमें से 1451 मामलों को बेहद गंभीर श्रेणी में डाला गया है।

कोरोना की खतरनाक होती स्थिति पर प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि लोग कोविड-19 की रोकथाम को बनाए नियमों को ताक पर रख रहे हैं। इसकी वजह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने लोगों को आगाह किया है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो देश मुश्किल में घिर जाएगा। लोगों के सवालों का जवाब देते हुए और देश के नाम संदेश देते हुए इमरान खान ने कहा कि सरकार इस बात को लेकर मजबूर हो रही है कि पाबंदियों को बढ़ाया जाए, क्योंकि लोग महामारी के प्रति लापरवाह हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने खुद महसूस किया है कि लोग सड़कों

पर निकलते हुए किसी तरह का नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोगों का ये रवैया पूरे देश को मुश्किल में डाल देगा। हम लोगों पर पाबंदियां नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बचाना जरूर चाहते हैं। इमरान खान ने ये भी कहा कि वो लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। इससे हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और इसका बुरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यदि मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो हमें इसके लिए भी मजबूर होना पड़ सकता है।

पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि देश पहले से ही कोविड-19 समेत दूसरी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसकी वजह से आर्थिक हालात सही नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई नहीं जानता है कि देश में आई कोरोना की तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी, लेकिन ये सच है कि ये पहली दो लहर से अधिक घातक जरूर है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो कोविड-19 की रोकथाम को बनाए सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करें। यही उनके लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर हैं। इसलिए किसी भी तरह की गलती जानलेवा हो सकती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बढ़ते मामलों के मद्देनजर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने इंटर प्रोविजनल ट्रांसपोर्ट को 10 से 25 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया है। पाकिस्तान में हर रोज 4700 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। फरवरी 2021 से ही वहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं।

## रूस से ट्विटर को राहत, फिलहाल नहीं होगा ब्लॉक, लेकिन अगले महीने तक स्पीड रहेगी कम

**मॉस्को।** रूसी अधिकारियों ने कहा कि वे मई के मध्य तक ट्विटर की गति धीमी रखेंगे, लेकिन फिलहाल इस इंटरनेट मीडिया मंच को ब्लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि उसने प्रतिबंधित सामग्री को तेजी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। रूसी सरकार और इंटरनेट मीडिया मंच के बीच हाल में जारी खींचतान के बाद इस घोषणा को राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

ट्विटर पर आरोप है कि उसने रूस में विरोध बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। रूस के सरकारी संचार निगरानीकर्ता रोस्कोम्नादजोर ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि ट्विटर बच्चों को आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाली सामग्री हटाने में विफल रहा है। इसके अलावा वह बाल यौन सामग्री और मादक पदार्थ संबधी जानकारी भी नहीं हटा सका। एजेंसी ने 10 मार्च को घोषणा की थी कि वह मंच पर तस्वीर और वीडियो अपलोड करने की गति सीमित कर रही है और एक हफ्ते से कम समय बाद ही धमकी दी कि अगर उसकी मांगें नहीं मानी गईं तो वह इंटरनेट मीडिया मंच को एक महीने के भीतर ब्लॉक कर देगी।

# दिल्ली में लगाया गया नाइट कर्फ्यू

## साथ ही छूट का भी हुआ एलान

**नई दिल्ली।** दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के मद्देनजर मंगलवार रात से कर्फ्यू लगाने का एलान हुआ है। आगामी 30 अप्रैल तक लगाए गए नाइट कर्फ्यू के तहत रात 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों को घर से निकलने पर मनाही होगी। दिल्ली सरकार से जुड़े एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को ही कहा था कि रात के कर्फ्यू लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन था। दिल्ली आपदा प्राधिकरण के मुताबिक, दिल्ली में आगामी 30 अप्रैल तक कर्फ्यू की समयावधि रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तय की गई है। इस दौरान तमाम तरह के प्रतिबंध रहेंगे। इसके मकसद कोरोना वायरस के खतरे और प्रभाव को फैलने से रोकना है। नाइट कर्फ्यू में रात से सुबह तक लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने-फिरने की मनाही होती है। यह टाइमिंग हर सरकार के अनुसार बदल भी जाता है। दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। इस दौरान लोग बेवजह घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। दरअसल पिछले दिनों महाराष्ट्र में कोरोना के बेकाबू होते हालात पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन किया है। वीकेंड लॉकडाउन के तहत रोजाना रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक सामान्य गतिविधियों पर रोक है। इस दौरान सरकारी दफ्तरों में 50 फीसद क्षमता के साथ काम होगा, निजी दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए हैं। फिल्मों एवं धारावाहिकों की शूटिंग होती रहेगी, लेकिन भीड़ की संभावना वाले सीन से बचने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, अंतिम संस्कार में 20 और विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

**इन्हें मिली छूट**

- निजी डॉक्टर
- नर्स
- पैरामेडिकल स्टाफ
- प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया के पत्रकार
- जो यात्री एयरपोर्ट जा रहे होंगे उन्हें भी छूट हासिल है, बशर्ते वह - अपना टिकट दिखाएं।
- नाइट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक सामान्य रहेगा यानी लोग अन्य - राज्यों से आ सकेंगे।
- नाइट कर्फ्यू में भी लोग कोरोना का टीका लगवा सकेंगे, लेकिन उन्हें इसके लिए पास लेना होगा।
- ई-पास लेकर सब्जी और फल विक्रेता, मेडिकल से जुड़े लोग आ-जा सकेंगे।
- पेट्रोल पंप ओर मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे।

स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे, सब्जी मंडियां खुली रहेंगी। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली में कोरोना के संक्रमण की चौथी लहर चल रही है, लेकिन लॉकडाउन लगाने पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि हम लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं और इस तरह का निर्णय उचित सार्वजनिक परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। यहां पर बता दें कि पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन लगाने की संभावना को पूरी तरह से खारिज तो नहीं किया था, लेकिन यह भी कहा था कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन लगाने की नौबत आई तो बातचीत कर इस पर फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। चार माह बाद संक्रमण दर 5.54 फीसद पहुंच गई है, जो 125 दिन में सबसे अधिक है। इसके पहले पिछले एक दिसंबर को संक्रमण दर 6.85 फीसद थी। अब एक बार फिर संक्रमण दर साढ़े पांच फीसद के पार पहुंच गई। इस वजह से दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो गया है।वहीं, बताया जा रहा है कि रविवार को कम सैंपल की जांच होने के कारण सोमवार को 3,548 नए मामले आए। संक्रमण बढ़ने के कारण सक्रिय मरीजों की संख्या 14,500 से अधिक हो गई है। इस वजह से अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। स्थिति यह है कि पिछले 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत हो गई। इस वजह से पिछले पांच दिन में कोरोना के कारण 69 मरीजों की मौत हुई है।

## छात्र को गोली मारने का आरोपित साथियों समेत गिरफ्तार, सामने आया प्रेम-प्रसंग का मामला

**नई दिल्ली।** अलीपुर इलाके में रविवार की रात डीयू के छात्र को उसके महिला मित्र के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मारी थी। मुख्य आरोपित अपनी बहन और छात्र की दोस्ती व बातचीत करने से नाराज था। उसने पीड़ित को पूर्व में बहन से बातचीत नहीं करने को लेकर धमकी भी दी थी। इस बाबत अलीपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर वारदात के कुछ घंटों बाद मुख्य आरोपित विक्रांत उर्फ नोनू व उसके साथी विकास पांडेय उर्फ भूरा व आशीष को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने इनके पास से वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व कारतूस, पिस्टल आदि बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसर 18 वर्षीय करन थापा अलीपुर के स्वामी श्रद्धानंद कालेज में बीए प्रथम का छात्र है। वह परिवार के साथ नेहरू एंक्लेव में रहता है। वह रविवार की रात अपने घर के पास खड़ा था। तभी बाइक पर आए तीन युवकों पर उस पर फायरिंग शुरू कर दी। उसे तीन गोलियां लगीं। स्वजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

वहीं, रानी बाग थाना पुलिस ने गत तीन माह के अंदर ताबड़तोड़ झपटमारी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपित मोतिया खान निवासी समीर (18) को गिरफ्तार किया है। उसके पास से वारदात में प्रयुक्त केटीएम मोटरसाइकिल व एक स्कूटी बरामद की गई है। उसकी गिरफ्तारी से झपटमारी के 39 मामले की गुत्थी सुलझा ली गई है। पुलिस उसके साथी की तलाश कर रही है। दोनों पकड़ में नहीं आए, इसके लिए मोटरसाइकिल बदल बदल कर वारदात किया करते थे।

## दिल्ली में अब तक 12 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका : सत्येंद्र जैन

**नई दिल्ली।** स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने कहा कि दिल्ली के निजी और सरकारी अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। लगभग 5000 बेड्स कोरोना के मरीजों के लिए बढ़ाए जा रहे हैं ।सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना संकरण पर पूरी तरह नजर बनाई हुई है ।इसके अलावा अब दिल्ली के 33 सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे कोरोना की वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। सत्येंद्र जैन ने आगे कहा कि उम्मीद है कि केंद्र सरकार मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का संज्ञान लेगी, ताकि सभी को वैक्सीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को लागू किया जा सके। सत्येन्द्र जैन ने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाई गई है और कल दिल्ली के अन्दर 65 हज़ार से भी ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए हैं । दिल्ली सरकार ने कल सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का आदेश दिया है। सरकारी और निजी अस्पतालों में 5,000 बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि ÷दिल्ली में कल 87,673 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है, जो की अब तक सर्वाधिक आंकड़ा है। राजधानी के अन्दर चल रहे वैक्सीनेशन के तहत कल हुए वैक्सीनेशन का लगभग 73त्न यानी 63,936 लोगों ने अपना वैक्सीनेशन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में करवाया। इसके अलावा 23,737 लोगों ने अपना टीकाकरण दिल्ली के निजी अस्पतालों में करवाया द्ध सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन का 95त्न टाइम स्लॉट प्रयोग किया गया वहीं निजी अस्पतालों में यह 67त्न प्रयोग किया गयाद्ध इससे हमें यह पता चलता है की लोग सरकारी अस्पतालों में जाकर अपना टीकाकरण करवाना ज्यादा पसंद कर रहे हैंद्ध दिल्ली के अंदर अबतक 12 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। सत्येंद्र जैन ने आगे कहा कि ÷पिछले कुछ महीनों में पहली बार संक्रमण का दर 5त्न से ऊपर गया है। दिल्ली सरकार बढ़ते संक्रमण के मामले को लेकर पूरी तरह सतर्क है और इस पर नजर बनाए हुए है। पूरे देश में भी यह संक्रमण का दर 5त्न से ऊपर ही है।

दिल्ली में 24 घंटे कोरोना वैक्सीन की सुविधा पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के सभी 33 सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे कोरोना वैक्सीनेशन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा केंद्र सरकार को सभी आयु वर्गो के लोगों का वैक्सीनेशन करने के लिए पत्र लिख कर दिए गये सुझाव को लेकर जैन ने कहा कि ÷अभी तक सिर्फ 45 साल या उससे ज्यादा आयु के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने की इजाजत है। सभी वर्गों के लोगों का वैक्सीनेशन करने से ही सभी लोगों का फायदा होगा, क्योंकि नौजवान उम्र के लोगों को कोरोना संक्रमण से खतरा तो कम रहता है लेकिन वह अपने परिवार के लिए संक्रमण वाहक का काम करते हैं। हमें लगता है कि सभी लोगों का एक साथ टीकाकरण करने से ही सर्वोत्तम प्रभाव पड़ेगा ।हमें आशा है की सीएम का सुझाव केंद्र सरकार द्वारा गौर किया जाएगा।

कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के अंदर सभी अस्पतालों में सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तत्पश्चात वैक्सीनेशन की सुविधा बिना रजिस्ट्रेशन के दिल्ली के अस्पतालों में उपलब्ध है। दिल्ली सरकार के पास लोगों का टीकाकरण करने के लिए पर्याप्त वैक्सीन है।

## पति की हत्या में आरोपित महिला को जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार

**नई दिल्ली।** पति सुबोध जैन की हत्या की साजिशकर्ता पत्नी प्रीति जैन ने तीन बच्चों की देखभाल करने के लिए मानवीय आधार पर जमानत याचिका दायर की है। वहीं, अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में पेश सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि प्रीति ने सुबोध की हत्या के लिए एक व्यक्ति के साथ मिलकर साजिश रची। होटल के रजिस्टर में भी महिला ने खुद को एक अन्य आरोपित की पत्नी बताया। इसके अलावा घर की एक चाभी आरोपित राहुल जैन व दूसरी प्रीति के पास से बरामद हुई। फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार दोनों ही चाभी एक समान हैं। इतना ही नहीं फोरेंसिक रिपोर्ट में यह भी साफ हुआ है कि घटनास्थल से बरामद दस्ताने का टुकड़ा एक अन्य आरोपित विजय कुमार के पास से मिले टुकड़े से मेल खाता है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने कहा कि उक्त सबूतों से साफ है कि याची घटना की मुख्य साजिशकर्ता है और उसे जमानत नहीं दी जा सकती है।

वहीं, आरोपित प्रीति जैन ने अधिवक्ता एलएस चौधरी के माध्यम से याचिका दायर कर नियमित जमानत की मांग की थी। असल में प्रीति जैन पर आरोप है कि उसने राहुल जैन व विजय कुमार के साथ मिलकर पति की हत्या की। मामले में तीन मई, 2019 को न्यू उस्मानपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी। वहीं, प्रीति ने याचिका में कहा कि वह बेकसूर है और उसे झूठा फंसाया गया है। आरोपित प्रीति जैन ने मानवीय आधार जमानत की मांग की। उसने दलील दी कि उसके 13 साल, 9 साल और 6 साल के तीन बच्चे हैं। उसकी गिरफ्तारी के कारण उनकी एक बेटी यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है, जबकि अन्य बेटी बीमारी से ग्रस्त है। उसने दलील दी कि उसके तीनों बच्चे ननद और देवर के पास हैं और वे बच्चों की सही तरीके से देखरेख नहीं कर रहे हैं। वहीं, अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि महिला के राहुल जैन के साथ अवैध संबंध थे और उसने राहुल व विजय के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी।

अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि राहुल कुमार ने सुबोध को मारने की सुपारी हरियाणा के गोहाना के आदर्श नगर निवासी विजय कुमार को 1.50 लाख रुपये में दी थी। यह सभी 29 अप्रैल, 2019 को मिले थे और राहुल ने प्रीति को नींद की दस गोलियां दी थीं। एक मई, 2019 को प्रीति ने सुबोध के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थीं और राहुल को इसकी जानकारी देकर बच्चों को लेकर ससुराल चली गई थी। राहुल के कहने पर विजय सुबोध के घर पहुंचा और उसकी हत्या कर दी।

## सिंघु बॉर्डर छोड़कर पंजाब लौटने लगे धरने पर बैठे किसान

**बाहरी दिल्ली।** इस समय गेहूं की फसल पक कर तैयार हो चुकी है। कई जगह गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो गई है तो कई जगह गेहूं मंडियों में खरीदे भी जा रहे हैं। इस वजह से प्रदर्शनकारी अब सिंघु बार्डर छोड़कर पंजाब जाने लगे हैं। क्योंकि उनको पता है कि यहां बैठकर कोई फायदा नहीं है। नतीजन प्रदर्शनकारियों की संख्या में एक बार फिर से गिरावट शुरू हो गई है। जो लोग बचे हैं, वह नेताओं के नजदीकी हैं। चाह कर भी घर नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए वह ट्रालियों या टेंट में बैठ कर समय काट रहे हैं। मायूसी उनके चेहरों पर साफ दिखाई देती है। ऐसे में सिंघु बार्डर पर दिल्ली की सीमा में ड्यूटी दे रहे कृषि कानून विरोधियों को बैठा कर रखना नेताओं के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। मजबूरन उनको मंच से कहना पड़ रहा है कि घर में चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे फसल खेतों

इस समय गेहूं की फसल पक कर तैयार हो चुकी है। कई जगह गेहूं मंडियों में खरीदे भी जा रहे हैं। इस वजह से प्रदर्शनकारी अब सिंघु बार्डर छोड़कर पंजाब जाने लगे हैं। क्योंकि उनको पता है कि यहां बैठकर कोई फायदा नहीं है।

में ही बर्बाद हो जाए, वह यहां से नहीं जाएंगे। ऐसा तब हो रहा है जब बीते कई दिनों से कोई बड़ा नेता सिंघु बार्डर पर मौजूद नहीं है। न तो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी (पंजाब) के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू और न ही महासचिव सरवन सिंह पंधेर मंच पर पहुंच रहे हैं। इससे इन नेताओं की मंशा साफ जाहिर हो रही है कि इन्हें न तो गेहूं की फसल से कोई मतलब है और न ही लोगों से। इन्हें सिंघु बार्डर को बंद करके लोगों को परेशान करने से मतलब है। अमृतसर व तरनतारन के गांवों के प्रदर्शनकारी यहां पर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शन में हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर लोग बदल रहे हैं। 15 दिन कुछ गांवों के लोगों की ड्यूटी यहां पर रहने के लिए लगाई जाती है तो 15 दिन दूसरे गांव के लोगों की। अब जब इन प्रदर्शनकारियों की ड्यूटी पूरी हो गई है तो नेताओं की सांस फूल रही है। उधर किसानों के मुद्दों को लेकर गुजरात पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को किसानों का साथ नहीं मिला। गुजरात में राकेश टिकैत ने अपने दूसरे दिन की यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर की। उनके साथ कांग्रेस किसान संगठन तथा शंकर सिंह वाघेला के गिने-चुने कार्यकर्ता ही नजर आए। जिस अपेक्षा के साथ किसान नेता ने गुजरात आने की घोषणा की थी, उनकी यात्रा के दौरान किसानों में उतनी ही उदासीनता नजर आई। पूर्व मुख्यमंत्री एवं इस यात्रा के योजनाकार वाघेला को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि किसान इस बार उनके समर्थन में सड़कों पर नहीं उतरेंगे। साबरमती आश्रम से उनकी किसान यात्रा सरदार पटेल की जन्म स्थली करमसद पहुंची। मगर किसानों की संख्या एकदम ही कम रही।

## सिर्फ वर्चुअल तरीके से सुनवाई के संबंध में नहीं जारी किया कोई नोटिस : हाई कोर्ट

**नई दिल्ली।** दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि उनके द्वारा ऐसा कोई नोटिस नहीं जारी किया गया कि छह अप्रैल से 17 अप्रैल तक सिर्फ वर्चुअल तरीके से ही मामलों की सुनवाई होगी। अधिवक्ताओं के विभिन्न वाट्सएप ग्रुप में साझा हो रहे एक नोटिस पर रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने यह स्पष्टीकरण दिया। रजिस्ट्रार कार्यालय ने साफ किया कि ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। सवालों के घेरे में आए उक्त पत्र में वर्चुअल तरीके से मामलों की सुनवाई शुरू होने के अलावा यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 मार्च से पूरी तरह से सामान्य प्रक्रिया के तहत सुनवाई शुरू कर दी थी। साथ ही यह भी कहा था कि वर्चुअल और हाई-ब्रीड सुनवाई अधिवक्ता के अनुरोध पर की जाएगी।

## हापुड़ में महापंचायत को संबोधित करने बैलगाड़ी से पहुंचे राकेश टिकैत

**नई दिल्ली।** कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे भारतीय किसान यूनियन(अराजनैतिक) के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत मंगलवार को महापंचायत को संबोधित करने के लिए बैलगाड़ी पहुंचे। महापंचायत बुलंदशहर रोड स्थित पड़ाव की जमीन पर हो रही है। महापंचायत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार, महापंचायत दोपहर दो बजे से होनी थी लेकिन राकेश टिकैत अब पहुंचे हैं। महापंचायत थोड़ी देर में ही शुरू होगी। इस महापंचायत के लिए संगठन के जिलाध्यक्ष ने प्रशासन से अनुमति मांगी थी। जिसे देर रात अनुमति भी मिल गई। प्रशासन ने दो सौ लोगों को महापंचायत में शामिल होने की इजाजत दी है। इसके साथ ही कोरोना नियमों का पालन करने को भी कहा गया है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कृषि सुधार कानूनों का विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर संगठन के लोग

तीनों कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को धार देने की कोशिश में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत एक बार फिर से जुट गए हैं। राकेश टिकैत आज हापुड़ में दो बजे महापंचायत को संबोधित करेंगे।

गाजीपुर बार्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत विभिन्न राज्यों और जनपदों में घूम-घूमकर महापंचायत कर रहे हैं। वह कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। महापंचायत में अधिक से अधिक किसानों को बुलाने के लिए संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव घूमकर संपर्क किया गया था। उपजिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने बताया कि भाकियू के जिलाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ने महापंचायत का आयोजन कराने की सूचना दी है। इसकी अनुमति के लिए उन्होंने आवेदन किया है। जिसकी जांच के लिए पुलिस क्षेत्रधिकारी धौलाना को निर्देशित किया था। उन्होंने कहा कि अनुमति शर्तों के साथ ही दी जाएगी। सीओ से रिपोर्ट न मिलने के कारण सोमवार शाम तक अनुमति नहीं दी जा सकी थी। राकेश टिकैत की महापंचायत को सफल बनाने के लिए गांव टियाला, असौड़ा, दादरी, जोगीपुरा, सुल्तानपुर, सलाई गांव में पहुंचकर गांव वालों को जागरूक किया गया था। साथ ही गांव वालों ने ज्यादा संख्या में पहुंचने का भरोसा दिया।

## साजिश के मामले में आरोपितों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पेश करने का आदेश

**नई दिल्ली।** दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में चल रहे सभी आरोपितों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के दौरान पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि आरोपितों के वकील कोर्ट में शारीरिक रूप से पेश होकर पक्ष रखेंगे। कोर्ट ने आरोपित पूर्व पार्षद इशरत जहां की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को निर्धारित है। आरोपित इशरत जहां ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में अर्जी दायर की थी। जिसमें उसने जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होने की इजाजत मांगी थी। सोमवार को कोर्ट ने उसकी अर्जी स्वीकार करते हुए जेल प्रशासन को निर्देश जारी कर दिया कि इशरत जहां को अगली सुनवाई से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये ही पेश किया जाए। इस मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आरोपित देवांगना कलीता

और नताशा नरवाल को पहले से आनलाइन माध्यम से पेश किया जा रहा है। इस पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे अन्य आरोपितों को भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से ही पेश किया जाए। इस मामले में दंगे के मुख्य आरोपित ताहिर हुसैन, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, जेएनयू छात्र शरजील इमाम समेत 16 आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं। आरोपित सफूरा जरगर जमानत पर है। एक आरोपित फैजान के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वांटर जारी कर रखा है। पिछली बार उमर खालिद ने सुनवाई पर लाते वक्त कड़ी सुरक्षा की मांग की थी। बात दें कि दंगे में नाम आने के बाद से ताहिर हुसैन को आप निलंबित कर चुकी है।

## दिल्ली में एक झील का ऐसा हाल, बरसात का पानी बनाता है झील, आम दिनों में लोग फेंकते हैं कूड़ा

**पश्चिमी दिल्ली।** पिछले एक दशक से तिहाड़ झील में पानी ही नहीं है। कभी बारिश के पानी से लबालब रहने वाला यह झील अब मैदान में तब्दील हो चुका है। झील में बारिश के मौसम को छोड़कर पानी की एक बूंद भी कहीं नजर नहीं आती है। बारिश के मौसम में भी झील के कुल हिस्से के दस फीसद भाग में ही पानी की थोड़ी बहुत मात्र नजर आती है। बारिश के बीतते ही यह पानी भी सूखी धरती में समा जाती है। कभी पर्यटन के लिहाज से दिल्ली विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार तिहाड़ झील की दुर्दशा सरकारी विभागों की ओर से जल संरक्षण को लेकर समय समय पर कहे जाने वाले वादों की पोल खोलकर रख देती है। तिहाड़ झील के आसपास पिछले पांच छह वर्षों से रहने वाले लोग तो अब यह बात भी बड़ी मुश्किल से मानते हैं कि यहां कभी झील होती थी। झील के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि करीब एक दशक से यहां नौकायन नहीं हो रहा है। अधिकांश समय सूखी रहने वाली इस झील में बारिश के समय भी इतना पानी नही रहता है कि इसमें नौकायन की सुविधा मिले। लोगों का कहना है कि कुछ वर्ष तो किनारों पर बोट नजर आए, लेकिन पिछले करीब एक दशक से एक भी बोट नजर नहीं आया जबकि कभी यहां छह बोट थे। डीडीए के स्वामित्व वाला तिहाड़ झील लगभग 50 एकड़ विस्तृत भूखंड में फैला है। इसके 32 एकड़ क्षेत्रफल पर पार्क है। जबकि छह एकड़ में जलग्रहण है। इसके अलावा लगभग आठ एकड़ क्षेत्र में बड़े हरित क्षेत्र है। तिहाड़ गांव निवासी भजन सिंह का कहना है कि डीडीए की ओर से यहां भूजल स्तर को बढ़ाने के उपाय गंभीरतापूर्वक कभी नहीं किए गए।

## पंजाबी बाग इलाके में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा

## टेंपो सवार शख्स की मौत

**नई दिल्ली।** पंजाबी बाग थाना क्षेत्र से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर निर्माणाधीन पुल का गार्टर गिर गया। गार्टर के हिस्से पुल के नीचे खड़े कुछ टैंपो के उपर जाकर गिरे। इनमें एक टैंपो में सो रहे शख्स की मौत हो गई। मृतक का नाम राम बहादुर 50 है। पुलिस का कहना है कि यह हादसा पुल का निर्माण करने वाली एजेंसी की लापरवाही के कारण हुआ है। संबंधित एजेंसी के बारे में पता करके उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस अभी यह पता करने में जुटी है कि पुल का निर्माण कितने दिनों से रुका हुआ था। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वर्ष 2017 से ही यहां काम रुका है। हालांकि रेलवे की ओर से इस बात पुष्टि नहीं की गई है। उधर रेलवे प्रशासन का कहना है कि लाइन के नीचे जो वाहन खड़े थे वे अवैध रूप से यहां खड़े थे। यह हादसा पंजाबी बाग के पास स्थित दया बस्ती रेलवे स्टेशन के लिए बन

रहे ग्रेड सेपरेटर लाइन पर हुआ है। यह रेलवे लाइन जमीन के उपर से पीलर के सहारे गुजर रही है। रामपुरा गोल्डन पार्क अंडरपास के पास जिस जगह हादसा हुआ है कि वहां लाइन के नीचे काफी वाहन खड़े रहते हैं। राम बहादुर यहां गार्ड का काम करते थे। यहां रात करीब दस बजे पीलर के उपर स्थित गार्टर ढहकर गिर गया। जब लोगों को यह पता चली तो सभी मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि गार्टर कुछ वाहनों के उपर गिरा है। इसके बाद लोग अपने घर चले गए। उधर जब सुबह राम बहादुर ड्यूटी के बाद अपने घर नहीं पहुंचे तो स्वजन को कुछ संदेह हुआ। स्वजन व मोहल्ले के लोग घटनास्थल पर उनकी तलाश के लिए पहुंचे। इस बीच लोगों ने मामले से पुलिस को भी अवगत करा दिया। मौके पर पुलिस, आपदा प्रबंधन व अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने पाया कि एक टैंपो पर गार्टर का बड़ा हिस्सा गिरा हुआ है। इसके अंदर पैर नजर आने के बाद गार्टर को टैंपो से हटाने का प्रयास किया गया। फिर हाइड्रोलिक क्रेन के सहारे गार्टर को हटाया गया। जिसके बाद पुलिस ने शव बरामद किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि रात में ही बचाव कार्य शुरू होता तो शायद राम बहादुर की जान बच सकती थी। लेकिन रात के समय किसी ने राम बहादुर को ढूंढ़ना जरूरी नहीं समझा। लोगों का कहना है कि रात को लगा कि राम बहादुर कहीं चले गए हैं, इसलिए उनकी तलाश नहीं की गई। इस मामले में एक सवाल यह है कि रात को हुए हादसे की जानकारी पुलिस को तत्काल क्यों नहीं मिली। क्या पुलिस का अपना तंत्र किसी हादसे के बारे में सूचना के लिए पूरी तरह दूसरों पर आश्रित है। क्षेत्र में गश्त करने वाले पुलिसकर्मियों को हादसे की जानकारी क्यों नहीं मिली। ऐसे कई सवाल हैं जिनकी तलाश छानबीन के दौरान होगी।

# संपादकीय

## स्पेनिश फ्लू की राह पर कोरोना

देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। कम से कम छह राज्यों में संक्रमण की रफ्तार तेज है और कई अन्य सूबों में भी ऐसी ही आशंका जताई जाने लगी है। गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में देश में 72,330 नए मामले सामने आए, जो रोजाना के नए संक्रमण के हिसाब से 11 अक्तूबर, 2020 (उस दिन 74,383 नए मरीज मिले थे) के बाद से सर्वाधिक है। साफ है, हम अब कोरोना की दूसरी लहर से मुकाबिल हैं। संक्रमण में यह तेजी स्पेनिश फ्लू की याद दिला रही है, जिसकी गिनती आज भी सबसे घातक वैश्विक महामारियों में होती है। सन 1918 में जब पहले विश्व युद्ध का अंत हो रहा था, तब स्पेनिश फ्लू पश्चिम से पूरी दुनिया में फैला था। तकरीबन एक तिहाई वैश्विक आबादी की अकाल मौत इससे हुई थी। अप्रैल-मई के महीनों में यह महामारी तेजी से ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और इटली में फैली थी। इसमें मृत्यु दर सामान्य मौसमी फ्लू की तरह ही थी, लेकिन अगस्त के महीनों से जब इसकी दूसरी लहर आई, तो वह कहीं ज्यादा घातक साबित हुई। दूसरे चरण में नौजवान भी इससे खूब प्रभावित हुए, और अगले दो महीने में मृत्यु दर आसमान पर पहुंच गई। भारत भी इन सबसे अछूता नहीं था। यहां की करीब छह फीसदी आबादी इसकी वजह से बेमौत मारी गई थी। यहां भी वैश्विक ट्रेंड के मुताबिक, 1918 की गरमियों में यह महामारी कम घातक थी, जबकि सर्दियों में यह ज्यादा मारक हो गई थी। करीब दो साल तक स्पेनिश फ्लू ने दुनिया को परेशान किया था, इसीलिए कोविड-19 के भी लंबा खिंचने की आशंका जताई जा रही है। कई दूसरे देशों में ऐसा दिख भी रहा है।

दिक्कत यह है कि अपने यहां अब मानव संसाधन की कमी खलने लगी है। मसलन, पिछले साल सरकार ने जब कोरोना के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी, तब स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ गैर-स्वास्थ्य कर्मचारी भी मोर्चे पर लगाए गए थे। अब इन कर्मियों की अपने-अपने विभाग में वापसी हो चुकी है, क्योंकि सभी सरकारी व सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं फिर से बहाल हो गई हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी भी सर्जरी जैसी गैर-कोविड सेवाओं पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, क्योंकि उनका 'बैकलॉग' काफी बढ़ चुका है। इसके कारण 'टेस्ट, ट्रैक ऐंड ट्रीट' (जांच, संक्रमितों की खोज और इलाज) जैसी कोरोना की बुनियादी सेवाओं के लिए स्वास्थ्यकर्मियों की कमी होने लगी है। समुदाय के स्तर पर भी बचाव संबंधी उपायों के प्रति उदासीनता साफ-साफ दिखने लगी है। ऐसा मालूम पड़ता है कि लोग अब इस महामारी से लड़ते-लड़ते थक से गए हैं। उनकी निश्चिंतता बताती है कि सरकार को कुछ नए प्रयास करने होंगे, ताकि जनता इस महामारी के खतरे की गंभीरता को समझ सके। अब शादी और अन्य सामाजिक उत्सव 'सुपर स्प्रेडर इवेंट' (कहीं तेजी से संक्रमण फैलाने वाले आयोजन) बनने लगे हैं। इस नई लहर में युवा व किशोर भी तेजी से बीमार हो रहे हैं। शिक्षण संस्थानों के खुलने और नौजवानों में सामाजिक संपर्क बढ़ने के कारण संभवतः ऐसा हो रहा है। चिंता की बात यह भी है कि ग्रामीण इलाकों में यह वायरस पसरने लगा है, जबकि वहां पिछले चरण में कमोबेश नहीं के बराबर संक्रमण थे। इससे स्वाभाविक तौर पर छोटे जिलों या कस्बों की स्वास्थ्य सेवाओं पर अप्रत्याशित बोझ बढ़ गया है, जो पहले से ही बेहाल हैं। इन सबका अर्थ यह है कि पिछले एक साल में सरकार ने जितना ध्यान इलाज और अनुसंधान संबंधी कार्यों पर दिया, उतना सामाजिक व्यवहार संबंधी एहतियातों पर नहीं दिया। अब इस असंतुलन को पहचानने और दुरुस्त करने का वक्त है। तभी जोखिम से जुड़ी संचार-योजना व समाज को जोड़कर महामारी से निपटने की रणनीतियां बनाई व लागू की जा सकती हैं। इनसे टीकाकरण के प्रति लोगों की हिचकिचाहट कम हो सकती है और टीके की मांग भी बढ़ सकती है। वैक्सीन को लेकर लोगों की कायम दुविधा कोरोना के खिलाफ हमारी जंग को कमजोर कर देगी।

सवाल यह है कि इस नई लहर से पार पाने के लिए क्या हमें फिर से लॉकडाउन का सहारा लेना होगा? देश के कुछ हिस्सों में यह रणनीति अपनाई भी गई है। मगर ऐसी किसी योजना को लागू करने से पहले हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में लॉकडाउन का सहारा लिया जा सकता है? कई शहरों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां के अस्पताल कोरोना मरीजों से भरने लगे हैं, मगर अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि अस्पताल मरीजों के अत्यधिक बोझ से हांफने लगे हैं। इसीलिए अस्पतालों की दशा देखकर लॉकडाउन पर फैसला किया जाना चाहिए। सरकारों को यह समझना होगा कि अभी लोगों में बचाव से जुड़ी व्यवहार संबंधी जागरूकता फैलाने की जरूरत है, न कि 'दंडात्मक उपाय' के रूप में लॉकडाउन लगाने की। अभी इससे बचने की आवश्यकता है, लेकिन छोटे शहरों में इसकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वहां स्वास्थ्य सेवाएं बहुत जल्द दम तोड़ने लगती हैं। हां, प्रसार को थामने के लिए छोटे-छोटे 'कंटेन्मेंट जोन' जरूर बनाए जाने चाहिए, ताकि संक्रमण की शृंखला तोड़ी जा सके। उम्मीद टीकाकरण से भी की जा सकती है। हालांकि, सवाल यह है कि कितनी तेजी से यह संभव हो सकेगा? भारत में 16 जनवरी को ही टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी, और बीते 75 दिनों में टीके की 6.43 खुराक लोगों को दी जा चुकी है। अब तक खास-खास वर्गों को ही टीका दिया गया है, लेकिन जिन 30 करोड़ लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया था, उनमें से महज 20 फीसदी का ही अब तक टीकाकरण हो सका है। शेष 80 फीसदी लक्षित आबादी को 120 दिनों में टीके लगाने की जरूरत होगी, जिसके लिए हमें भगीरथ प्रयास करने होंगे। और हमारी यह कोशिश तभी सफल हो सकती है, जब समाज टीकाकरण के प्रति उत्साहित हो और इसकी मांग बढ़े। जाहिर है, यह सरकार और जनता के आपसी विश्वास व उपयुक्त समन्वय-संवाद से ही संभव हो सकेगा।

प्रवीण कुमार सिंह

## श्रीलंका में रहने वाले तमिल मूल के लोगों पर भारत की दुविधा

> इसी पृष्ठभूमि में भारतीय प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्र हुई, जहां उनके द्वारा सागर नीति की घोषणा की गई और श्रीलंका के साथ संबंधों को नए सिरे से परिभाषित किया जाने लगा। दूसरी ओर श्रीलंका निरंतर चीन के कर्ज जाल में फंसता गया और हंबनटोटा बंदरगाह चीन के पास जाने के बाद उसकी संप्रभुता पर ही प्रश्न उठने लगे। अतः श्रीलंकाई सरकार वर्तमान में सामरिक स्वायत्तता की नीति के आधार पर अपनी विदेश नीति को विविधीकृत करने का प्रयास कर रही है, जिससे चीन पर बढ़ती निर्भरता कम की जा सके।

पड़ोसी देशों के प्रति भारत का रवैया हमेशा से उदार रहा है। भारत ने श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों को मानवतावादी सहायता प्रदान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वर्तमान परिदृश्य के तहत थोड़ा पीछे जाएं तो 1956 में श्रीलंका सरकार ने 'सिंहलीज ओनली बिल' पारित किया जिसका मुख्य उद्देश्य तमिलों को उनके अधिकारों से वंचित करना था, ताकि सिंहली बहुसंख्यक समुदाय का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रभुत्व बना रह सके। वर्ष 1972 में श्रीलंका का नया संविधान निर्मित किया गया और तमिलों की अपेक्षाएं इसमें भी पूरी नहीं की गईं।

नए संविधान में सिंहली को राष्ट्रभाषा और बौद्ध धर्म को आधिकारिक मान्यता दी गई। तमिलों ने अपने लिए जिन मांगों को श्रीलंका सरकार के समक्ष रखा था उनको नहीं माना गया। उनकी मुख्य मांगें हैं ः प्रथम श्रेणी की नागरिकता का दर्जा, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हिस्सेदारी के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक आर्थिक नियोजन में हिस्सेदारी, तमिल भाषा को आधिकारिक मान्यता, तमिल संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली के साथ भेदभाव और हस्तक्षेप न करने की मांग, बुनियादी सुविधाओं और अवसंरचनाओं के निर्माण की मांग जिसमें प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सड़क, कृषि आदि शामिल थे।

इसी क्रम में श्रीलंकाई सेना ने 1976 के बाद लिट्टे विद्रोहियों का भीषण दमन करना शुरू किया। तमिल स्वायत्तता की मांग के साथ तमिलों ने सिंहलियों की हत्याएं भी कीं। वर्ष 1983 में कोलंबो में तमिल विरोधी हिंसा शुरू हो गई। तमिलों के मारे जाने से तमिलनाडु की भावनाएं आहत हुईं। उस समय भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वायु मार्ग और समुद्री जहाजों से तमिलों को खाद्य सामग्री, दवाइयां और अन्य आवश्यक रसद सामग्री उपलब्ध

कराई थी। तब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन ने इसके लिए नई दिल्ली जाकर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात कर उन्हें 1971 के पूर्वी पाकिस्तान के प्रकरण में भारतीय सहायता के तर्ज पर तमिलों को सहायता देने का निवेदन किया था। इसी समय जब भारत सरकार को एक रिपोर्ट के जरिये सूचना मिली कि श्रीलंका सरकार ने तमिल सिंहली विवाद में अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सहायता का निवेदन किया है तो भारत के विदेश मंत्री ने दो अगस्त, 1983 को विभिन्न विदेशी शक्तियों से श्रीलंका के नृजातीय संघर्ष के मामले से बाहर रहने का आग्रह किया। पाकिस्तान जो कथित तौर पर श्रीलंका के गृहयुद्ध में राहत सहायता और सैन्य सहायता उपलब्ध करा रहा था, उसे इस संघर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई अवसर भारत नहीं देने का पक्षधर था। इंदिरा गांधी ने कहा था कि तमिलों के साथ किए जाने वाले अन्याय की स्थिति में भारत मूकदर्शक नहीं बना रह सकता। 29 जुलाई 1983 को भारतीय विदेश मंत्री नरसिंह राव को श्रीलंका भेजा गया, ताकि हालात का सही मूल्यांकन किया जा सके। भारत के इन सब सक्रिय पहलों को श्रीलंका और सिंहलियों ने अपने आंतरिक मामलों, संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता का अतिक्रमण समझा। कालांतर में भारत ने तमिल पृथकतावादियों और श्रीलंका की सरकार के मध्य मध्यस्थता कराने का प्रयास किया। इधर 1987 तक लगभग डेढ़ लाख श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी भारतीय राज्य तमिलनाडु में आ चुके थे।

इसके बाद अस्तित्व में आए राजीव-जयवर्धने एकॉर्ड के क्रियान्वयन के लिए श्रीलंका का 13वां संविधान संशोधन लाया गया जिसमें तमिलों की मांग को पूरा करने के लिए अनेक प्रविधान किए गए। इसमें तमिल क्षेत्रों में वित्तीय मामलों और उनके हितों को सुनिश्चित करने के लिए वित्त आयोग के गठन का भी प्रविधान किया गया। इस समझौते में तमिल को श्रीलंका की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप में इसमें उत्तरी पूर्वी प्रांत में उच्च न्यायालयों की स्थापना का भी प्रविधान किया गया। साथ ही, 13वें संविधान संशोधन के तहत श्रीलंका को नौ प्रांतों में वर्गीकृत किया गया जिसका प्रशासन एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले परिषद द्वारा किया जाना था। इस संशोधन के तहत उत्तर और पूर्वी प्रांत का विलय कर एक एकल उत्तर पूर्वी प्रांत बनाया गया। इसके बावजूद 13वें संविधान संशोधन के कई प्रविधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है जिससे तमिल स्वायत्तता की मांग सही अर्थो में अभी भी पूरी नहीं हो सकी है। भूमि और वित्तीय अधिकार अभी भी तमिलों को प्रदान नहीं किया गया है। श्रीलंका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति ने भी जनवरी 2020 में स्पष्ट किया कि 13वें संविधान संशोधन के कुछ प्रविधानों को लागू नहीं किया जा सकता और श्रीलंका सरकार कुछ वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करेगी।

श्रीलंका सरकार का साथ देने का औचित्य ः वर्तमान भू-अर्थ प्रधान विश्व में दक्षिण एशिया उभरती अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र बनता जा रहा है। ऐसे में भारत अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों के साथ विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और सहयोग के अवसरों की तलाश पर अधिक बल दे रहा है। भारत का प्रयास सुरक्षा प्रदायक और विकास भागीदार के रूप में पड़ोसी देशों में विद्यमान बिग ब्रदर सिंड्रोम को दूर करने के लिए भी जारी है। इस संदर्भ में भारत के लिए भौगोलिक रूप से रणनीति के केंद्र में अवस्थित श्रीलंका महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन दोनों देशों के परंपरागत संबंध तमिल संकट, मछुआरों से संबंधित विवाद जैसे मुद्दों के कारण अविश्वास और पूर्वाग्रह पर आधारित रहे हैं। हालांकि तमिल अतिवादी संगठन लिट्टे की समाप्ति के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार की व्यापक उम्मीद जताई गई थी, लेकिन इस दौरान भी भारत की घरेलू राजनीति और तमिल क्षेत्रीय दलों के दबाव के कारण भारत की श्रीलंका से दूरी बनी रही।

इस संदर्भ में वर्ष 2003-2009 के मध्य श्रीलंका में हुए गृहयुद्ध में श्रीलंकाई सेना पर निर्दोष तमिलों के गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगा था। जबकि इसी दौरान चीन द्वारा न केवल मानवाधिकार उल्लंघन के प्रश्न पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर श्रीलंका का समर्थन किया गया, बल्कि गृहयुद्ध और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित श्रीलंका की कमजोर अर्थव्यवस्था को व्यापक स्तर पर आर्थिक मदद भी दी गई। परिणामस्वरूप श्रीलंका चीन पर अत्यधिक निर्भर होता गया और भारत के स्वाभाविक क्षेत्र में चीन का नियंत्रण बढ़ता गया। लेकिन वर्ष 2014 के बाद दोनों देशों के संबंधों में फिर से सकारात्मक बलवाव आया। वर्ष 2014 में भारत में एक पूर्ण बहुमत की सरकार गठित हुई, अतः अब तमिल क्षेत्रीय दलों की भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में भूमिका नहीं रही। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्र हुई, जहां उनके द्वारा सागर नीति की घोषणा की गई और श्रीलंका के साथ संबंधों को नए सिरे से परिभाषित किया जाने लगा। दूसरी ओर श्रीलंका निरंतर चीन के कर्ज जाल में फंसता गया और हंबनटोटा बंदरगाह चीन के पास जाने के बाद उसकी संप्रभुता पर ही प्रश्न उठने लगे। अतः श्रीलंकाई सरकार वर्तमान में सामरिक स्वायत्तता की नीति के आधार पर अपनी विदेश नीति को विविधीकृत करने का प्रयास कर रही है, जिससे चीन पर बढ़ती निर्भरता कम की जा सके। अतः वर्तमान श्रीलंका सरकार भारत से संबंधों को प्राथमिकता दे रही है। श्रीलंका भारत के विकासात्मक सहायता के प्रमुख प्राप्तकर्ता देशों में से एक है। भारत ने विकासात्मक सहयोग के नाम पर श्रीलंका को तीन अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता तय कर रखी है जिसमें से 56 करोड़ डॉलर अनुदान के रूप में है। एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध श्रीलंका भारत और समूचे दक्षिण एशिया के लिए जरूरी है। इसलिए भारत ने श्रीलंका में विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने की रणनीति वहां 2009 में गृहयुद्ध खत्म होने के समय से अपना रखी है।

## दिल्ली में फैक्ट्री लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाने की ओर ध्यान दे सरकार

वर्तमान कानूनों की समय समय पर बदलती सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार समीक्षा नहीं होने से किस प्रकार अनेक कानूनी प्रविधान अप्रासंगिक और अनुपयोगी बनकर नागरिकों के लिए कष्टदायक हो जाते हैं। हालांकि ऐसे कई मामले हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली नगर निगम का फैक्ट्री लाइसेंस से संबंधित मामला इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 416 (1) के अनुसार, दिल्ली में किसी भी औद्योगिक इकाई की स्थापना करने से पूर्व निगम आयुक्त से लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। इसी अनुमति को फैक्ट्री लाइसेंस कहा जाता है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 416 (2) के अनुसार आयुक्त मात्र दो कारणों से यह अनुमति देने से इन्कार कर सकता है। पहला, आबादी का घनत्व और दूसरा यदि प्रस्तावित औद्योगिक इकाई के कारण आस-पड़ोस से कोई बाधा उत्पन्न हो।

ऐसे में पहले यह जानना आवश्यक है यह प्रविधान क्यों बना दरअसल वर्ष 1957 में जब दिल्ली नगर निगम अधिनियम लागू हुआ तब दिल्ली में एक भी अधिकृत औद्योगिक क्षेत्र नहीं था और किसी भी स्थान पर उद्योग लग सकता था। अतः शहर के व्यवस्थित विकास की दृष्टि से यह प्रविधान तब आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, उस समय पानी और बिजली की आपूर्ति भी नगर निगम के पास थी। अतः इन सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित करना आवश्यक था।

अब हम आज की स्थिति को समझते हैं। आज दिल्ली का औद्योगिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। आज दिल्ली में 29 अधिकृत एवं 22 अधिसूचित यानी कुल 51 ओद्योगिक क्षेत्र हैं जो मात्र उद्योग लगाने के लिए ही स्थापित, विकसित, आवंटित और निर्धारित किए गए हैं। इनके बाहर

अब दिल्ली में कोई उद्योग स्थापित नहीं हो सकता। इससे यह स्वतः स्पष्ट है किनिगम आयुक्त द्वारा अनुमति से इन्कार कर सकने के उपरोक्त दोनों आधार दशकों पहले ही अर्थहीन और अप्रासंगिक हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त पानी, बिजली, प्रदूषण, अग्निशमन और औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण आदि समेत उद्योगों से जुड़े सभी विषयों का नियमन करने के लिए अलग अलग स्वतंत्र विभाग या अधिकरण बने हुए है। उद्योगों के संचालन से जुड़ा कोई भी विषय अब नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। फैक्ट्री लाइसेंस दशकों से भ्रष्टाचार और उत्पीड़न का पर्याय बना हुआ है, लेकिन कानूनी समीक्षा के अभाव और निहित स्वार्थवश इसे अब तक लागू रखा गया है।

यद्यपि कहने को इस लाइसेंस की प्रक्रिया लगभग गत एक दशक से ऑनलाइन हो गई है, लेकिन इसकी जटिल प्रक्रिया के कारण गत 63 वर्षो में दिल्ली के कुल उद्योगों में से अब तक 25 प्रतिशत इकाइयों को भी यह जारी नहीं हुआ है। उसमें से भी आज प्रभावी लाइसेंसों की संख्या तो और भी कम है, क्योंकि नवीनीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। इस मद से निगमों को नगण्य आय होती है, जबकिउनके फैक्ट्री लाइसेंस विभागों पर प्रति वर्ष करोड़ों रुपये निर्थक खर्च होते हैं।

इसके आगे की कहानी तो और भी रोचक है। लघु उद्योग भारती सहित दिल्ली के अनेक औद्योगिक संगठन दशकों से फैक्ट्री लाइसेंस के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। वर्ष 2015-16 में दिल्ली के तीनों नगर निगमों के सदनों ने फैक्ट्री लाइसेंस को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिल्ली सरकार को यह कहते हुए भेज दिया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम संसद का कानून है, अतःइसे संसद द्वारा संशोधित करने हेतु आगे की कार्रवाई की जाए। लेकिन इस संबंध में अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है।वर्ष 2018 में लघु उद्योग भारती ने यह विषय केंद्रीय शहरी विकास मंत्रलय के समक्ष उठाया। मंत्रलय ने सभी संबंधित पक्षों यथा नगर निगम आयुक्तों, गृह मंत्रलय व दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि से पर्याप्त विचार-विमर्श करने के पश्चात जुलाई 2019 में फैक्ट्री लाइसेंस को कानून संशोधन के द्वारा समाप्त करने की संस्तुति गृह मंत्रलय को भेज दी, लेकिन नगर निगमों, राज्य और केंद्र सरकार की उदासीनता एवं नीहित स्वार्थी तत्वों द्वारा बार-बार उत्पन्न अड़चनों के कारण एक अत्यावश्यक जनहितकारी कार्य गृह मंत्रलय के स्तर पर आज तक अधूरा पड़ा है।

वर्ष 2017 में संपन्न दिल्ली नगर निगमों के चुनाव के समय जारी अपने घोषणा पत्रों में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ने फैक्ट्री लाइसेंस को दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में समाप्त करने का वादा किया था, लेकिन दिल्ली के लाखों उद्यमी आज तक इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिल्ली में कल-कारखानों की स्थापना करने के लिए सक्षम प्राधिकरण से लाइसेंस हासिल करना पड़ता है, जो अब व्यावहारिक नहीं है, लिहाजा इस व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए।

## छापों में राजनीति का रंग

तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए होने वाले मतदान के ठीक पहले डीएमके नेता एमके स्टालिन की बेटी, पार्टी के अन्य नेताओं और उनसे जुड़े लोगों पर आयकर विभाग के छापे पड़े। इससे एक बार फिर यह आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी अपने राजनीतिक हित साधने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस आरोप के जवाब में कहा जा सकता है कि अगर किसी के खिलाफ शिकायतें आती हैं और कोई एजेंसी जांच शुरू करती है तो फिर उस प्रक्रिया को किसी भी बात से क्यों प्रभावित होना चाहिए। अगर बीच में कोई चुनाव वगैरह आ जाते हैं तो क्या सिर्फ इसीलिए वह जांच रोक दी जाए? %कानून को अपना काम करने देना चाहिए% का बहुप्रचारित तर्क इस सवाल का जवाब ना में देता है और सत्तारूढ़ दल आम तौर पर विरोधियों की आलोचना को शांत करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते आए हैं। बात तो यह भी सही है कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग कोई आज से शुरू नहीं हुआ है। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दौरान ही

सीबीआई को पिंजरे के तोते का तमगा मिला था। लेकिन बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि यह पुरानी रीत बदलेगी। मगर देखने में यह आया कि ऐसी शिकायतें कम होने के बजाय और बढ़ गईं।

कुछ अरसा पहले की ही बात है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार अंदरूनी चुनौतियों की वजह से संकट में थी। तभी गहलोत के करीबी नेताओं पर आयकर विभाग के छापे पड़ने लगे। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव तक हो चुके हैं। कुछ राज्य बगैर इजाजत सीबीआई के अपने यहां आने पर पाबंदी लगा चुके हैं। यह बात भी छिपी नहीं है कि राजनीति में आरोपों का जवाब आरोपों से देकर काम चला लिया जाता है। लेकिन यहां मूल सवाल राजनीति का नहीं, देश की जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता का है। हमारी जांच एजेंसियां ठीक से जांच करके वास्तविक दोषियों तक पहुंचें और उन्हें कानून के मुताबिक सजा दिलाएं, यह जितना जरूरी है, उतना ही आवश्यक यह भी है कि वे ऐसा करते हुए नजर आएं। इससे उनके तौरतरीकों और नीयत को लेकर किसी के मन में संदेह नहीं रह जाएगा। अब अगर यह मान भी लें कि तमिलनाडु में जिन मामलों में शुक्रवार को छापे मारे गए, वे सचमुच गंभीर थे, तब भी यह सवाल बना रहता है कि क्या ये मामले ऐसे थे कि दो-तीन दिन रुक जाने से जांच पटरी से उतर जाती? क्या छह अप्रैल को मतदान हो जाने का इंतजार ये अफसर नहीं कर सकते थे ताकि इन छापों को राजनीतिक रंग देने की कोई गुंजाइश ही न बचती?

## देश में डिजिटलीकरण से तेज होगा आर्थिक विकास, व्यावहारिक रूप से बढ़ावा देना जरूरी

> ऐसे में भारत को अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। यह सही है कि डिजिटलीकरण प्रतिस्पर्धी फायदे के पारंपरिक सिद्धांत को खत्म कर देगी। लिहाजा विनिर्माण क्षेत्र में भी तेजी से डिजिटल तकनीक को अपानाया जा रहा है। समझना होगा कि अर्थव्यवस्थाओं को किसी भी निर्णायक प्रतिस्पर्धी लाभ का फायदा उठाने के लिए प्रासंगिक, मजबूत और अद्यतन तकनीक में निरंतर निवेश करने की आवश्यकता होगी। आज डिजिटल दुनिया तुलनात्मक लाभ के नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। जबकि हम तकनीक में निवेश करने के लिए एकत्रीकरण और संसाधनों के संग्रहण के लिए जूझ रहे हैं।

हमारे देश की आबादी में यदि वर्तमान गति से वृद्धि जारी रही तो आगामी तीन दशकों में यह आंकड़ा दो अरब तक पहुंच सकता है। हम असीमित विकास की ओर आगे अवश्य बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे नागरिकों का एक बड़ा वर्ग अर्थव्यवस्था के 'सबसे निचले पायदान' पर स्थित है। मध्य वर्ग हमेशा की तरह 'प्रदाता' की भूमिका में है, फिर भी उसकी ओर अपेक्षाकृत सबसे कम ध्यान दिया जाता है। यह सही है कि सक्षम लोग विकास और बड़े पैमाने पर सरकार को फायदा पहुंचाते हैं। साथ ही, यह भी सही है कि अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति संसाधनों पर एकाधिकार रखते हैं और जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उनका वर्चस्व कायम रहता है। ऐसे में यह भी स्पष्ट होता है कि भारत की समस्या वृद्धिशील सोच से हल नहीं हो सकती है। इसके लिए नवोन्मेष को बढ़ावा देना होगा।

यहां तक कि अगर हम आठ प्रतिशत की दर से वृद्धि करते हैं तो भी हम कई आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। हमें विशेष रूप से इस बात की चिंता करनी चाहिए कि समाज का सबसे गरीब तबका अभी भी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। इसी तरह यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने लगभग 50 प्रतिशत बुजुर्गों को आराम का जीवन, सामाजिक गरिमा और युवाओं को बेहतर भविष्य कैसे प्रदान करते हैं? गरीबी उन्मूलन, सभी के लिए स्वास्थ्य, योग्य लोगों को रोजगार, शिक्षा और समावेश के लिए काम तेज करना होगा।

आर्थिक तौर पर पिछले तीन दशकों को कई तरह से परिभाषित किया गया है और पिछली सदी के आखिरी दशक के आरंभिक दौर में शुरू किए गए आर्थिक सुधार वास्तव में परिवर्तनकारी थे। दरअसल यह वृद्धिशील विकास संसाधनों जैसे भूमि, श्रम तथा पूंजी के एकत्रीकरण व संकलन से प्रेरित था और एक सुधारवादी पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर स्थापित किया गया था। हालांकि कोरोना संक्रमण से प्रभावित अर्थव्यवस्था के दौर को छोड़ भी दें तो बीते कुछ वर्षो से विकास दर धीमी हो गई है, जो चिंतनीय है और आर्थिक विकास के इस मॉडल में सामयिक बदलाव को इंगित करता है।

हमारे नीति निर्माताओं को सतर्क और चुस्त व दूरदर्शी बनने की आवश्यकता है। उन्हें एक नए प्रतिमान गढ़ने की जरूरत है। अगले दशक के लिए एक अलग सोच और योजना की जरूरत है। ऐसे में नीति निर्माताओं को तकनीकी क्रांति के बारे में समझना और उसे स्वीकार करना चाहिए। हमने अक्सर नौकरशाही को देर से प्रतिक्रिया देते हुए देखा है। लेकिन समय की मांग है कि आगामी कई दशकों को ध्यान में रखते हुए हमारे नीति निर्माताओं को इस दिशा में व्यावहारिक कदम उठाने की जरूरत है।

आज दुनियाभर में डिजिटल तकनीक एक 'सामान्य उद्देश्य' के रूप में उभर रही है यानी एक ऐसी तकनीक जो लगातार रूपांतरित होती है, तेजी से बढ़ती है और हर क्षेत्र में उत्पादकता लाभ को बढ़ा रही है। अपेक्षित विकास से आवधिक विस्तार और स्थायी उन्नति में तेजी आती है, जो मजबूत और दीर्घकालिक फायदे सृजित करती है। इसे पाने का प्रभावी तरीका है सवरेत्तम साधनों, संसाधनों व ज्ञान को आगे बढ़ाना और अवसरों का सदुपयोग करना। स्मार्टफोन व कंप्यूटर के माध्यम से बैंकों तक सभी की घर बैठे आसान पहुंच और तमाम विधाओं में घर से काम करने के प्रारूप के तौर पर बीते लगभग एक वर्ष से हमने इसका अनुभव भी किया है। तकनीक ने वित्तीय उद्योग में लोगों के लेन-देन के तरीके को बदल कर रख दिया है। आज बैंकों के अधिकांश क्रियाकलापों को डिजिटल तकनीक ने घर बैठे संभव बना दिया है। इससे वित्तीय समावेशन सशक्त बन रहा है।पिछले कुछ समय के चुनिंदा देशों के उदाहरणों को देखें तो ऐसा महसूस होता है कि भारत औद्योगिक क्रांति से चूक गया। ऐसा दक्षता, पारिस्थितिकी तंत्र और सुधार के बाद विकास को बढ़ाने के लिए आर्थिक पैमाने की कमी के कारण हुआ। दरअसल हमारी कमजोर और अर्थव्यवस्था की नाजुक प्रकृति, बाहरी लोगों (नौकरशाही व नियंत्रित सोच) का संयोजन हमें नीचे धकेलती है। जबकि दक्षता सशक्तीकरण से आती है। स्पष्ट है कि व्यापक क्षमता होने के बावजूद हम कुछ खास हासिल नहीं कर सके हैं। इसी तरह 25 करोड़ युवा भारतीयों में से अधिकांश क्षमतावान तथा शिक्षित होने के बावजूद रोजगार के मामले में लाचारी का सामना कर रहे हैं। बेरोजगारी एक महामारी के समान है, विशेष रूप से उत्तर भारत में। जबकि आज का युवा जागरूक है तथा ऊंची उड़ान भरना चाहता है। देश के करीब पांच करोड़ 'उद्यमी' और इस अर्थव्यवस्था के रोजगार संचालक एक ऐसे समाधान की तलाश कर रहे हैं, जो उनके व्यवसाय को बढ़ाए ताकि वे 'मध्यम स्थिति' से आगे बढ़ सकें। इतिहास में कई सबक छिपे हुए हैं। अल्पकालिक अव्यवस्थाओं के बावजूद, क्रांतिकारी तकनीकों के आसपास अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करना अल्पावधि में एक प्रेरक और दीर्घावधि में एक विशाल मल्टीप्लायर का काम करता है। हमारे नीति निर्माताओं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री की इस बात के लिए सराहना करनी चाहिए कि भारत को दुनिया की 'फैक्ट्री' बनाना स्वाभाविक पसंद नहीं है। कुछ अर्थो में हम उन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जिन्होंने तुलनात्मक लाभ प्राप्त किया है। ऐसे में भारत को अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। यह सही है कि डिजिटलीकरण प्रतिस्पर्धी फायदे के पारंपरिक सिद्धांत को खत्म कर देगी। लिहाजा विनिर्माण क्षेत्र में भी तेजी से डिजिटल तकनीक को अपानाया जा रहा है। समझना होगा कि अर्थव्यवस्थाओं को किसी भी निर्णायक प्रतिस्पर्धी लाभ का फायदा उठाने के लिए प्रासंगिक, मजबूत और अद्यतन तकनीक में निरंतर निवेश करने की आवश्यकता होगी। आज डिजिटल दुनिया तुलनात्मक लाभ के नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। जबकि हम तकनीक में निवेश करने के लिए एकत्रीकरण और संसाधनों के संग्रहण के लिए जूझ रहे हैं।

यह सही है कि स्वचालन आधारित विकास में न केवल नौकरियों की संख्या में कमी आती है, बल्कि यह विस्थापित भी हो सकता है, यहां तक कि अकुशल और सघन-श्रम उत्पादों और कार्यो की मांग भी कम कर सकता है। लेकिन इसके अन्य कई लाभकारी पहलू भी हैं, जिनके बारे में हमें समग्रता से विचार करना चाहिए।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

# मुख्तार अंसारी के साथ षड्यंत्र को लेकर बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी आशंकित

**लखनऊ ।** बाहुबली मुख्तार अंसारी की पंजाब के रोपड़ से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में करीब 14 महीने बाद वापसी कराने उत्तर प्रदेश पुलिस का भारी भरकम बल रुपनगर जेल पहुंचा है। इसी बीच मुख्तार अंसारी के बड़े भाई गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने बड़े षडयंत्र की आशंका जताई है। अफजाल अंसारी ने कहा है कि उनको कानून-व्यवस्था पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत में खोट है।

सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि उन्हें कानून पर तो पूरा यकीन है, लेकिन उत्तर सरकार की नियत में खोट नजर आ रहा है। इसके कारण हमारा पूरा परिवार मुख्तार अंसारी को लेकर बेहद चिंतित है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने नेता लगातार इस बाबत गैर-जिम्मेदाराना बयान दे कर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ ही भाजपा के कई विधायकों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी लोग तथा सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया प्रभारीगण भी लगातार जिस तरह से विधायक मुख्तार अंसारी के बारे में बयानों दे रहे हैं, उससे वह चिंतित है।

उन्होंने कहा कि मुख्तार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत भले ही बेहद खराब है, लेकिन उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उनको यकीन है कि मुख्तार अंसारी को एक दिन इंसाफ मिलेगा। अफजाल अंसारी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी बाहुबली ब्रजेश सिंह के खिलाफ मुख्तार अंसारी काफी मुखर हैं, इसी कारण ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मेरे भाई के खिलाफ बड़ा षडयंत्र कर रही है।

गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में रखे जाने के दौरान ही षड्यंत्र रचे जाने की आशंका जताई है। हमारा परिवार मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर मीडिया रपट तथा भाजपा नेताओं के बयान के कारण आशंकित है।

उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाकर उत्तर प्रदेश की जेल में रखे जाने पर उसके साथ कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है। अफजाल अंसारी ने कहा कि जब राज्य सरकार ही सुरक्षा पर संकट उत्पन्न कर रही है तो हमारे पास न्यायपालिका की शरण में जाने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं बचता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मीडिया रपट व भाजपा नेताओं के बयानबाजी को देखते हुए मुख्तार अंसारी के सुरक्षा मसले का स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें देश की स्वतंत्र न्यायपालिका पर गर्व है, देश में अभी न्याय जिंदा है। अफजाल ने मुख्तार अंसारी पर मुस्लिम देशों से फंडिंग के आरोप को लेकर जांच की चुनौती दी है। भाजपा की केंद्र व राज्य में सरकार है, इसकी जांच किसी भी एजेंसी से कराई जा सकती है।

अफजाल अंसारी ने कहा कि मुख्तार को लाइये। मुकदमा चलाइये, इससे किसको इनकार है। कोरोना के कारण तमाम कोर्ट में विचाराधीन बंदी को फिजिकली पेशी से रोक है। सभी की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हो रही है। तो क्या मुख्तार अंसारी की पेशी नहीं हो सकती है। अफजाल अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार को यूपी भेजने का आदेश दिया है। उसे किस तरह से यूपी लाया जाएगा, इस पर तो कुछ नहीं कहा है।

## लखनऊ में धारा 144 लागू, पंचायत चुनाव तथा कोरोना संक्रमण को लेकर पांच मई तक सख्ती

**लखनऊ ।** राजधानी लखनऊ में नियंत्रण के बाहर हो रहे कोरोना वायरस के नए संक्रमण के साथ ही पंचायत चुनाव के कारण धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला तथा पुलिस प्रशासन को इसका सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। लखनऊ में पांच मई तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान एक स्थान पर पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और पंचायत चुनाव के कारण सूबे की राजधानी लखनऊ में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को धारा-144 का सख्ती से पालन कराने के निर्देश निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव और कोरोना के संक्रमण को बढ़ते देख धारा-144 का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए।

अब लखनऊ में एक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर एक्शन होगा। इसके साथ ही पंचायत चुनाव के प्रचार पर भी सख्ती की गई है। अब लखनऊ में धारा-144 पांच मई तक लागू रहेगी। लखनऊ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। लखनऊ में धारा-144 के सख्ती से पालन कराने का निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिया है। उन्होंने लखनऊ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए धारा-144 को लागू करने का फैसला लिया है।

लखनऊ में अब धारा-144 लगने के बाद जिले में एक जगह पर एक बार में पांच से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। पंचायत चुनाव के दौरान अगर कोई जुलूस निकालना है या फिर जनसंपर्क करना है तब पांच ज्यादा लोगों को शामिल करने के लिए पुलिस से अनुमति लेनी जरूरी होगी।

प्रदेश में अब रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का भी प्रयोग नहीं होगा। यहां पर सरकारी आदेश के मुताबिक, किसी भी धार्मिक स्थल पर रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर या ऐसा कोई भी यंत्र जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, जिससे किसी दूसरे समुदाय की धार्मिक भावना को आहत पहुंचती हो।

बिना अनुमति के नहीं होंगे सामाजिक कार्यक्रम~ लखनऊ में अब अगर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन कराना है तो उसके लिए जिला तथा पुलिस प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। इसके साथ ही कार्यक्रम में आने वाले लोगों की संख्या भी सीमित कर दी गई है।

अगर कोई कार्यक्रम बंद कमरे में होता है, तो वहां कमरे की क्षमता के हिसाब से 50 प्रतिशत लोग ही आ सकते हैं। अगर कार्यक्रम किसी खुले मैदान या खुली जगह में में होता है, तो वहां 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं।

## संक्षिप्त खबर

### अयोध्या के सरयू घाट पर पंचतत्व में विलीन हुआ शहीद, बेटे ने दी मुखाग्नि; अंतिम दर्शन को उमड़ा जन सैलाब

**अयोध्या ।** छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए रामनगरी के सपूत का राजकुमार यादव का पार्थिव शरीर सोमवार देर रात अयोध्या पहुंचा। बेटे का पार्थिव शरीर देख परिवार में कोहराम मच गया। इस दौरान शहीद के अंतिम दर्शन को चाहने वालों का तांता लगा रहा। मंगलवार सुबह जनसैलाब के साथ शहीद का पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार को सरयू घाट ले जाया गया। योगी सरकार ने शहीद परिवार को दिए 50 लाख~ उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर गति को प्राप्त शहीद के परिवार को 50 लाख भेंट किए। इसमें से 35 लाख शहीद की पत्नी वह 15 लाख शहीद की मां को दिए गए। दोनों के खाते में पैसे सोमवार ट्रांसफर कर दिए। यह जानकारी महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने दी है। वहीं, मुख्यमंत्री के सात अप्रैल को राम नगरी आने की भी संभावना है। इस दौरान वे शहीद परिवार से मिलने उनके आवास पर भी जा सकते हैं।

नक्सलियों से लिया था मोर्चा ~ बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर सीआरपीएफ की कोबरा 210 बटालियन में तैनात अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के रानोपाली बढ़ई टोला निवासी राजकुमार यादव ने भी नक्सलियों से मोर्चा लिया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए राजकुमार ने नक्सलियों ने दांत तो खट्टे कर दिए, लेकिन अंततः~ वह वीरगति को प्राप्त हुए। चार जुलाई वर्ष 1976 को रानोपाली निवासी सूरजलाल यादव के घर वीर सपूत राजकुमार यादव का जन्म हुआ था। वर्ष 1995 में वह सीआरपीएफ में नियुक्त हुए। वे ताइक्वांडो के शानदार खिलाड़ी भी रहे। दिसंबर में आए थे घर~ गत वर्ष दिसंबर में राजकुमार छुट्टियों पर घर आए थे। 11 जनवरी को देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए वह वापस ड्यूटी पर चले गए। दो दिन पहले ही वाट्सएप मैसेज के जरिये राजकुमार की अपने भाई रामविलास से वार्ता हुई थी, जिसमें उसने अपने परिवार का कुशलक्षेम जाना था।

### मासूम बच्ची को टॉफी का लालच देकर ले गए अपने साथ, फिर दो दरिंदों ने किया गंदा काम

**जीरादेई (सिवान) ।** थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार की देर शाम एक मासूम के साथ दो युवकों ने दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। टॉपी का लालच देकर बच्ची के साथ दोनों हैवानों ने दुष्कर्म किया। घटना को लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों आरोपित घर छोड़कर फरार हैं। मिली जानकारी के अनुसार मासूम अपने घर के सामने खेल रही थी। तभी गांव के दो युवक टॉपी का लालच देकर बहला-फुसलाकर बच्ची को सुनसान जगह पर ले गए। वहां पर उनलोगों ने हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। जब मासूम बच्ची देर रात घर नहीं पहुंची तो स्वजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इसी क्रम में किसी ने कहा कि दोनों युवकों के साथ उसे जाते देखा गया था। इसके बाद बच्ची के परिवार के लोग उन युवकों के घर पहुंचे। वहां बच्ची थी। वह अपने परिवार के लोगों को देखकर बिलखने लगी। तब घटना का पता चला। इसके बाद स्वजन पुलिस के पास पहुंचे।

**पीड़िता की बुआ के बयान पर प्राथमिकी दर्ज-** इस संबंध में पीड़िता की बुआ के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मासूम को मेडिकल टेस्ट के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

### पंजाब में 7 वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी, डॉक्टरों को निकालनी पड़ी बच्चेदानी

**अमृतसर ।** कपूरथला में दरिंदगी का शिकार हुई बच्ची का इलाज अमृतसर स्थित गुरुनानक देव अस्पताल में चल रहा है। दरिंदों ने बच्ची की टांग तोड़ा दी। साथ ही इतनी दरिंदगी की गई कि डॉक्टरों को उसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ी है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों को इंफेक्शन बढ़ने की वजह से ऐसा करना पड़ा है। बच्ची के पैरों पर प्लास्टर कर दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची को गला घोंटकर मारने का भी प्रयास किया गया था। बच्ची की हालत अभी स्थिर है। हालांकि परिजनों का कहना है कि दुष्कर्म पीड़िता बच्ची को सरकारी अस्पताल में निशुल्क उपचार नहीं दिया जा रहा। महंगी दवाइयां व जरूरी सामान बाहर से मंगवाया जा रहा है।

बच्ची से दरिंदगी की घटना 15 मार्च की है। भुलाणा में पड़ते आरसीएफ के बाहर बनी झुग्गियों में देर शाम 25 वर्षीय शादीशुदा युवक ने एक सात वर्षीय बच्ची को घर में अकेली देखकर अपनी हवस का शिकार बनाया। जैसे ही बच्ची के चिल्लाने की आवाज पड़ोसियों को सुनाई दी तो युवक मौके से फरार हो गया।थाना भुलाणा की चौकी के इंचार्ज़ एएसआइ गुरदीप सिंह द्वारा लड़की को सिविल अस्पताल कपूरथला में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। जैसे ही कपूरथला के एसएसपी कंवरदीप कौर, डीएसपी सब-डिवीज़न सुरिंदर सिंह, डीएसपी सुल्तानपुर लोधी सरवन सिंह बल, एसएचओ फतूढींगा सोनमदीप कौर को पता चला तो वह मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने लड़की का मेडिकल करवाया। छापामारी के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं, बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे कपूरथला सिविल अस्पताल से अमृतसर स्थित गुरुनानक देव अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां भी बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपित ने बच्ची से इतनी दरिंदगी की कि डॉक्टरों को उसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ी है।

आरोपित मुकेश कुमार ने बच्ची को बिस्कुट दिलाने के बहाने अपने पास बुलाया था। लड़की के पिता ने बताया कि आरोपित उसे खाली झुग्गी में ले गया था और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में लड़की के गुप्तांग में लकड़ी डाल दी। घटना के बाद पुलिस की तरफ से लड़की के पिता के बयानों के आधार पर मुकदमा नंबर 68 दर्ज किया गया, जिस पर आइपीसी की धारा 376,307,4 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया।

## सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा का ध्वज फहराया

**लखनऊ ।** भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश भाजपा ने भी लखनऊ में प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को आयोजन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वर्चुअल संबोधन किया। उनका संबोधन सुनने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल के साथ योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के सहयोगी भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के तहत भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह के साथ भाजपा का ध्वज भी फहराया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ तथा डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को इस दौरान सम्मानित भी किया।

कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने महानगर के साथ ही कैसरबाग में पार्टी के कार्यकर्ताओं के आवास पर जाकर भाजपा का ध्वज फराराया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पार्टी का स्थापना दिवस बूथ स्तर तक मना रही है। पार्टी के राज्य मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रीय, जिला, महानगर कार्यालयों व मण्डल स्तर पर कार्यकर्ता पार्टी के स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं।

भाजपा से बढ़ रहा गांव-गरीब का जुड़ाव~ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि आज भाजपा से गांव-गरीब का जुड़ाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज वो पहली बार अंत्योदय को साकार होते देख रहा है। आज 21वीं सदी में जन्म देने वाला युवा, भाजपा के साथ है, भाजपा की नीतियों, भाजपा के प्रयासों के साथ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के काम का मूल्यांकन उसके डिलिवरी सिस्टम से हो रहा है। यह देश में सरकारों के कामकाज का नया मूलमंत्र बन रहा है। बावजूद इसके, दुर्भाग्य है कि भाजपा

अगर चुनाव जीते तो उसे चुनाव जीतने की मशीन कहा जाता है।

उन्होंने कहा कि भाजपा को कार्यकर्ता ताकत देते हैं, जनता के बीच काम करते हुए संगठन की शक्ति को और बढ़ाते हैं। अपने जीवन, आचरण, प्रयासों से वो जनता का दिल जीतने का काम अविरत करते रहते हैं। कार्यकर्ताओं के प्रयासों से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सभी को भाजपा स्थापना दिवस की बहुत-बहुत बधाई। पार्टी के गौरवशाली यात्रा के आज 41 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि सेवा और समर्पण के साथ कोई पार्टी कैसे काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में राजनीतिक स्वार्थ के लिए दलों के टूटने के अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन देशहित में लोकतंत्र के लिए दल के विलय की घटनाएं शायद ही कहीं मिलेंगी। भारतीय जनसंघ ने यह करके दिखाया था। उन्होंने कहा कि हमारी कार्यशैली है हम किसी से छीनते नहीं, सबकी आवश्यकता पर संवेदनशीलता से काम करते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों का मुद्दा उठाया और कहा कि पहले की सरकारों की प्राथमिकता में छोटे किसान नहीं थे लेकिन हमारी सरकार ने छोटे किसानों की बेहतरी के लिए कई नए कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस क्रम में उन्होंने फसल बीमा योजना, अंत्योदय योजना आदि का जिक्र किया।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि मैं भाजपा के स्थापना दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। 1980 में भाजपा की स्थापना हुई थी। आज 41वां स्थापना दिवस हम सब मना रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आज भाजपा अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर उन्होंने सबका साथ, सबका विकास को भाजपा विश्वास का मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में भाजपा कभी दो सीट में थी और आज 303 सीट पर पहुंची। उन्होंने कोरोना काल के दौरान आई चुनौतियों का भी जिक्र किया। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को फूलों की श्रद्धांजलि अर्पित की।

## बिहार में मुखिया व उपमुखिया को हटाने को लेकर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, अब इनकी संस्तुति जरूरी

**पटना ।** पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि मुखिया या उप मुखिया को हटाने से पहले अगर लोक प्रहरी की संस्तुति नहीं ली गई है तो वैसी कार्रवाई गैर कानूनी होगी। अदालत ने हैरानी भी जताई कि पंचायती राज कानून में लोक प्रहरी की भूमिका होने के बावजूद आजतक इस संस्था का गठन नहीं किया गया। आज भी पंचायती राज संस्थाओं में लोक प्रहरी की अनुशंसा बगैर ही सरकार मुखिया पर कार्रवाई कर रही है।

**लोक प्रहरी की अनुशंसा जरूरी-** न्यायाधीश डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने कौशल राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि पद के दुरुपयोग के आरोप पर पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के आदेश से मुखिया को पदच्युत कर दिया गया। किंतु उक्त कार्रवाई करने में लोक प्रहरी से कोई संस्तुति नहीं ली गई। पंचायती कानून की संशोधित धाराओं में प्रावधान है कि मुखिया/उप मुखिया, प्रमुख को हटाने से पहले लोक प्रहरी की अनुशंसा जरूरी है।

एक दशक पहले ही पंचायती राज कानून में ऐसा संशोधन किया गया लेकिन आजतक लोक प्रहरी संस्था का गठन तक नही हुआ! नतीज़ा है कि राज्य सरकार के अधिकारी लोक प्रहरी की शक्तियों को खुद से धारण कर इस्तेमाल कर रहे हैं जो गैर कानूनी है। वहीं सरकारी मनमानेपन की बात भी सामने आई। याचिकाकर्ता सीतामढ़ी के डुमरी प्रखंड की बिशुनपुर ग्राम पंचायत के मुखिया थे। उसी प्रखंड के बरियारपुर पंचायत के मुखिया पर ज्यादा गंभीर आरोप होते हुए भी उन्हें केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया जबकि याचिकाकर्ता को उसके पद से हटा दिया गया। लोक प्रहरी जैसी संस्था के नही होने से अफसरशाही ऐसी मनमानी कर रही है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अर्जी को मंजूर करते हुए प्रधान सचिव के आदेश को निरस्त कर दिया।

**क्या था मामला-** याचिकाकर्ता सीतामढ़ी के डुमरा ब्लॉक स्थित बिशुनपुर ग्राम पंचायत के मुखिया थे। ग्रामसभा की बैठक से पारित निर्णय पर उसने हर घर नल का जल योजना के लिए 18 लाख रुपये की निकासी की, लेकिन कुछ महीने बाद भी योजना पर अमल नहीं हुआ तो उसने सूद सहित सरकारी राशि वापस बैंक में जमा कर दी। विभाग ने याचिकाकर्ता पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कार्रवाई कर उसे पदच्युत कर दिया था। कोर्ट ने इस कारवाई को पंचायती राज कानून के प्रविधानों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए याचिकाकर्ता को वापस पद पर बहाल करने का निर्देश दिया।

**क्या है लोक प्रहरी-** बिहार राज पंचायती एक्ट, 2011 की धारा 5 ऑफ 152 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि जिस प्रकार से लोकायुक्त का गठन होता है उसी के तर्ज पर एक लोक प्रहरी पद गठित किया जाएगा द्य लोक प्रहरी की अनुशंसा के बिना मुखिया एवं उप मुखिया को नहीं हटाया जा सकता है।

## यमुना एक्सप्रेस वे पर बदमाशों का आतंक, बस रोक कर की यात्रियों से लूटपाट

**आगरा ।** सफर के लिहाज से सुरक्षित माने जाने वाले यमुना एक्सप्रेस वे पर सोमवार देर रात बदमाशों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया। यमुना एक्सप्रेस वे पर सोमवार रात दिल्ली से हमीरपुर जा रही बस को सुरीर क्षेत्र में सवारी बनकर खड़े लुटेरों ने रुकवा कर जमकर लूटपाट की। हथियारों की दम पर बस में सवार दो दर्जन यात्रियों व परिचालक से हजारों की नकदी, जेवरात आदि सामान लूट ले गए। लूट की सूचना पर पुलिस महकमे में खलबली मच गई। आला अधिकारी मांट टोल पर मंगलवार सुबह पहुंच गए हैं।

चौहान ट्रेवल्स की बस यूपी 75 बीटी 0131 को चालक रफीक निवासी औरैया सोमवार रात दिल्ली से सवारियां लेकर यमुना एक्सप्रेस वे पर होकर हमीरपुर जा रहा था। बस में करीब 24 यात्री बैठे हुए थे। थाना सुरीर क्षेत्र में माइल स्टोन 88 के समीप सवारियों के रूप में खड़े आधा दर्जन लुटेरों ने रात करीब साढ़े 12 बजे बस को रुकवा लिया। बस में सवार होने के बाद लुटेरों ने करीब पांच सौ मीटर दूर जाकर बस को रुकवा लिया। यात्रियों से लूटपाट शुरू कर दी। एक-एक यात्री की तलाशी लेकर लुटेरे नकदी व जेवरात आदि कीमती सामान के अलावा परिचालक के बैग से 25 हजार रुपये लूटकर बस से कूदकर फरार हो गए। चालक बस को लेकर मांट टोल पर पहुंचा और घटना की जानकारी दी। बस लूट की सूचना से पुलिस में खलबली मच गई। लूटपाट के शिकार हुए यात्री पुलिस की कार्रवाई को लेकर असंतुष्ट थे। मंगलवार सुबह पुलिस हरकत में आई और लुटेरे के हुलिए के आधार पर तलाश शुरू कर दी है।

## भारत से नेपाल जाना अब मुश्किल, कोरोना संक्रमण को लेकर वीरगंज बार्डर सील

**पूर्वी चंपारण** (रक्सौल)। कोरोना संक्रमण को लेकर भारत-नेपाल सीमा पर काफी सख्ती है। नेपाल सरकार ने पर्सा जिला वीरगंज बार्डर सील कर रखा है। इस दौरान नेपाल में अवैध रूप से यानी बगैर इंट्री के कागजात के भारतीय वाहनों को जब्त किया गया है। पिछले करीब एक वर्ष में 41 लाख 60 हजार रुपये मूल्य के कीमती वाहनों को नेपाल पुलिस ने जब्त किया है। इसकी जानकारी पुलिस प्रवक्ता डीएसपी प्रह्लाद गिरि ने दी।बताया कि बार्डर सील है। इस परिस्थिति में नियम का उल्लंघन कर ग्रामीण रास्ते से नेपाल सीमा में प्रवेश करते भारतीय वाहनों को जब्त किया गया। इसमें ट्रक, बाइक, स्कूटी आदि वाहन अलग-अलग जगहों से जब्त किया गया है। जिसे नीलामी के लिए नेपाल भंसार यानी कस्टम को सौंपा जा रहा है। बता दें कि नेपाल मंत्रीमंडल के निर्णय के बाद स्थानीय नेपाल प्रशासन ने भारतीय वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी है।

करीब एक वर्ष से रोक जारी होने से भारतीय पर्यटक और स्थानीय लोग भारतीय वाहनों को लेकर नेपाल नहीं जा पा रहे हैं। भारत-नेपाल सीमा कोरोना संक्रमण को लेकर 13 माह से नेपाल ने सील कर रखा है। दो माह पूर्व नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल ने बार्डर खोलने का निर्णय लिया था। इसके बावजूद भारतीय वाहनों का नेपाल में प्रवेश नहीं हो रहा है। जबकि नेपाली वाहन निर्बाध गति से आ रहे हैं। नेपाल के सीमावर्ती पर्सा और बारा जिला के प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि बार्डर खोलने का निर्णय हुआ है। इसके लिए अधिकृत रूप से कोई पत्र और मेल नहीं मिला है।जबकि भारत या तीसरे देशों से आयात-निर्यात पर प्रतिबंध नहीं है। भारतीय वाहनों का प्रवेश नहीं होने से देशी-विदेशी पर्यटकों को नेपाल यात्रा को लेकर संशय है। भारत सरकार ने दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को देखते हुए सात माह पूर्व ही इंडो-नेपाल बार्डर को खोल दिया था। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्र के लोग चोरी-छिपे ग्रामीण रास्तों से नेपाली नंबर के बाइक और टैंपो से आवागमन कर रहे हैं।इस बीच रक्सौल अनुमंडल क्षेत्र या पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के लोग भारतीय नंबर के वाहनों से अवैध रूप से प्रवेश किया। जिसे नेपाल पुलिस जब्त कर नीलाम कर रही है।

## बिहार के मधुबनी में पांच लोगों की हत्या ने लिया राजनीतिक रंग

**मधुबनी ।** मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र स्थित महमदपुर गांव में होली के दिन पांच लोगों की हत्या के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। बयानबाजी हो रही है। अभी तक कई नेता यहां आ चुके हैं। सोमवार को पूर्व सांसद व राजद नेता रामा किशोर सिंह, शिवहर विधायक चेतन आनंद समेत अन्य नेता पहुंचे। इससे पहले पप्पू यादव भी पहुंचे थे। मंगलवार को दोपहर दो बजे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। घटना में करीब एक दर्जन आरोपितों को पुलिस जेल भेज चुकी है। दो मुख्य आरोपितों के घर कुर्की भी की जा चुकी है। कई आरोपितों के घर पुलिस ने इश्तेहार चस्पा किया है। शेष आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है।

**नीतीश राज में अपराधियों की खैर नहीं-** झंझारपुर के जदयू सांसद आरपी मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में बिहार में कानून का राज कायम है। अपराध के मुद्दे पर नीतीश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमेशा से कायम है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के महमदमुर गांव में घटी हत्याकांड ने मानवता को शर्मसार किया है।

हत्याकांड में संलिप्त अपराधियों को स्पीडी ट्रायल चलवाकर शासन-प्रशासन कठोर सजा दिलाएगी। कहा कि नीतीश कुमार के शासन में

अपराधियों की खैर नहीं है, चाहे अपराधी कितना भी रसूख वाला क्यों न हो। सांसद ने मृतकों के स्वजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उक्त हत्याकांड मधुबनी जैसे शांतप्रिय जिला के लिए कलंक के समान है। इस घटना ने मधुबनी जिला की गरिमा को रक्तरंजित किया है।

**अपराधियों की नहीं होती कोई जाति-धर्म-** पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने महमदपुर गांव जाकर पीड़ित परिवार से मिल सामुहिक हत्याकांड को दुखद व हृदय विदारक बताया। कहा कि अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कठोर से कठोर सजा दी जाए। कहा कि सामुहिक हत्याकांड की घटना में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहा कि अपराधियों की कोई जाति व धर्म नहीं होता है।

**महमदपुर हत्याकांड सरकार व प्रशासन के लिए कलंक**

जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि सूबे की सरकार अपराध के बल पर सत्ता में है। महमदपुर सामूहिक हत्याकांड दर्दनाक है। सरकार के चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर प्रश्न खड़ा हो रहा है। घटना के आठ दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस मुख्य आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। सत्ता के संरक्षण में अपराध की घटना हो रही है। जो भी पुलिस पदाधिकारी लापरवाह पाए गए, उनके विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। महमदपुर का सामुहिक हत्याकांड सरकार व प्रशासन के लिए कलंक है।

**राजनीतिक संरक्षण व भागीदारी की हो विशेष जांच** -राजद जांच टीम के सदस्य सह राजद विधायक चेतन आनंद ने कहा कि महमदपुर कांड में कुछ नए खुलासे सामने आए हैं। पीड़ित परिवार का स्पष्ट मानना है कि इसमे एक मंत्री और विधायक की संलिप्तता है। आरोपित प्रवीण झा जिनके लिए जमीन कब्जाने का काम करता रहा है। इसके कई साक्ष्य उपलब्ध हैं। मछली, शराब, हथियार आदि के वैध-अवैध धंधों में भी उसकी संलिप्तता रही है।

**अपराधी-प्रशासन की मिलीभगत का परिणाम सामूहिक हत्याकांड -** पूर्व सांसद रामा सहिं ने कहा कि इस सामूहिक हत्याकांड में प्रशासन के पदाधिकारी पर भी हत्या का मुकदमा होनी चाहिए। राजनीतिक संरक्षण देने वाले पर भी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। कहा, नीतीश की सरकार गुंडे व मवालियों की सरकार है। इतनी बड़ी सामुहिक हत्या के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन हैं। यदि इस हत्याकांड में पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो बिहार में ऐसा आंदोलन खड़ा होगा, जिसकी कल्पना सरकार नहीं कर सकती है।

**पुलिस तत्पर रहती तो नहीं होती इतनी बड़ी घटना-** पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता डॉ. शकील अहमद और पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक ने महमदपुर गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिल घटना को दुखद बताया है। डॉ. अहमद ने कहा कि पुलिस प्रशासन तत्पर रहती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। सामूहिक हत्या की घटना से मिथिला की बदनामी हुई है। होली के दिन हुई गोलीबारी की घटना में पांच लोगों की मौत हो गई है। घर उजड़ गए हैं। परिवार के बच्चे अनाथ हो गए हैं। इस घटना ने समाज को कलंकित किया है। कानून अपना काम कर रही है। इस हत्याकांड में संलिप्त अपराधी को कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए।

## एक नजर

### राजस्थान में बूथ कैप्चरिंग रोकने के लिए वेब कास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा

**जयपुर** । राजस्थान में 17 अप्रैल को तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उप चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार अभियान चरम पर है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर तैयारी तेज कर दी है। चुनाव में मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग और अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश करने सहित अन्य अवांछनीय गतिविधियों की संभवना को देखते हुए वेब कास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के लिए कठोर कदम उठाया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1145 मतदान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से 100 को संवेदनशील मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इन मतदान केंद्रों पर वेब कैमरों से नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 39,राजसमंद में 35 और सुजानगढ़ में 26 मतदान केंद्रों पर इस तकनीक के जरिए निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर लगे वेब कैमरों से प्राप्त सूचना पर त्वरित प्रभावी कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर सभी तकनीकी सुविधाओं से युक्त नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा भी इसे देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि वेब कैमरों के संस्थापन में भी इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि मतदान की गोपनीयता प्रभावित हुए बिना कक्ष के अंदर प्रवेश से लेकर मतदाता के बाहर निकलने तक की प्रत्येक गतिविधि रिकॉर्ड की जा सके।

### ओड़िशा बेकाबू हुआ कोरोना, 588 नए संक्रमितों की पुष्टि; खुर्दा में सर्वाधिक 105 नए मरीज

**भुवनेश्वर** । ओड़िशा में कोरोना धीरे-धीरे बेकाबू होता जा रहा है। पिछले दो दिनों से राज्य में 500 से अधिक संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। एक दिन पहले जहां प्रदेश में 573 नए मामले सामने आए थे तो वहीं आज 588 नए मामले सामने आए हैं। इसमें से 342 क्वारेनटाइन से हैं जबकि 246 स्थानीय लोग संक्रमित पाए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आज खुर्दा जिले से सर्वाधिक 105 नए मरीज सामने आए हैं जबकि अनुगुल जिले से 5, बालेश्वर जिले से 13, बरगड़ जिले से 21, भद्रक जिले से 9, बलांगीर जिले से 11, कटक जिले से 30, देवगड़ जिले से 4, ढेंकानाल जिले से 6, जगतसिंहपुर जिले से 3 लोग संक्रमित मिले हैं। उसी तरह से गजपति जिले से 1, गंजाम जिले से 27, जाजपुर जिले से 15, झारसुगुड़ा जिले से 31, कालाहांडी जिले से 64, कंधमाल जिले से 3, केन्दुझर जिले से 2, कोरापुट जिले से 9, मयूरभंज जिले से 9, नवरंगपुर जिले से 8, नयागड़ जिले से 7, नुआपड़ा जिले से 29, पुरी जिले से 24, रायगड़ा जिले से 6, सम्बलपुर जिले से 28, सोनपुर जिले से 11, सुन्दरगड़ जिले से 84 तथा स्टेटपुल में 23 लोग संक्रमित पाए गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक 3 लाख 43 हजार 856 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3 लाख 38 हजार 150 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं जबकि 3731 सक्रिय मामले हैं जिनका विभिन्न कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है।

### बालेश्वर की पांच पंचायतों के लोगों ने रास्ते के मरम्मत को लेकर जिलाधीश से लगायी गुहार

**बालेश्वर** । बालेश्वर के पांच पंचायतों के लोगों ने बालेश्वर के जिलाधीश से मुलाकात कर फुला डी नामक स्थान से लेकर चसा खंड तक के मुख्य रास्ते को मरम्मत किए जाने की मांग की है। यह रास्ता करीब पांच पंचायतों के विभिन्न गांव से जुड़ता है। इन लोगों की मांग है यदि हमारी मांगों पर एक सप्ताह के भीतर विचार न किया गया तो इसी महीने के 12 तारीख को 60 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा। इन लोगों का आरोप है कि समय-समय पर जब कोई नए जिलाधीश आते रहे हैं। यह लोग अपनी मांग उनके सामने रखते हैं क्योंकि फुला डी से लेकर चसा खंड वाले रास्ते पर ही भारत के महान सपूत शहीद बाघा जतिन और उनके पांच साथियों का स्मृति स्थल भी बना हुआ है। जहां पर प्रत्येक दिन पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से भारी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते है तथा दर्शन के लिए आते हैं लेकिन इस जर्जर रास्तों के चलते यह लोग दोबारा उक्त स्थान पर आना नहीं चाहते केवल सितंबर के महीने में शहीद बाघा जतिन के जयंती के उत्सव पर जिला प्रशासन की ओर से लाल मिट्टी रास्तों पर बिछाकर जिला प्रशासन अपना दायित्व समाप्त समझता है।
इन लोगों का आरोप है उक्त पंचायतों में एंबुलेंस से लेकर दमकल की गाड़ियां समय-समय पर नहीं पहुंच पाती क्योंकि रास्ते इतने जर्जर हो गए हैं कि फुला डी से लेकर चसा खंड के बीच घंटों लग जाते हैं। इन गाड़ियों को पहुंचने के लिए वहीं दूसरी ओर पड़ोसी जिला मयूरभंज के कलमा महिषासुर पुनिया तथा बालेश्वर के चसाखंड पंचायत के हजारों लोग बालेश्वर शहर इसी रास्ते से प्रत्येक दिन आना जाना करते हैं। विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी इसी रास्ते से होकर शहरी इलाकों तक पहुंचते हैं लेकिन जर्जर सड़कों के कारण आज लोगों का आना-जाना मानो पहाड़ सा लगने लगा है। इन लोगों ने जिलाधीश से गुहार लगाया कि जल्द से जल्द उक्त रास्ते का मरम्मत का कार्य ना किया गया तो इसी महीने के 12 तारीख को भी और 5 पंचायतों के करीब हजारों की तादाद में पुरुष और महिलाएं राष्ट्रीय राजमार्ग के आवागमन को पूरी तरह से ठप कर देंगे। यहां उल्लेखनीय है कि चसाखंड से रास्ते के बीच कई लोगों के व्यक्तिगत जमीन होने के कारण लोग अदालतों में मामले दर्ज किए हैं।

### बंगाल के उलबेरिया में तृणमूल नेता के घर से ईवीएम और वीवीपैट बरामद, सेक्टर ऑफिसर निलंबित

**कोलकाता** । हावड़ा जिले की उलबेरिया उत्तर विधानसभा सीट के तुलसीबेरिया इलाके में एक तृणमूल नेता के घर से ईवीएम और वीवीपैट बरामद हुए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर गौतम घोष नामक उक्त तृणमूल नेता के घर के सामने विरोध-प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब दो बजे स्थानीय सेक्टर ऑफिसर चुनाव आयोग की गाड़ी से ईवीएम और वीवीपैट लेकर तृणमूल नेता के घर पहुंचे थे। गाड़ी से उन्हें उतारते वक्त पड़ोस के कुछ लोगों को इसका पता चला तो उन्होंने इसका प्रतिवाद किया। इसके बाद वहां भाजपाइयों का जमावड़ा लग गया और उन्होंने विरोध-प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने सेक्टर ऑफिसर को अटका कर रखा। सेक्टर ऑफिसर का कहना है कि वे असिस्टेंट सेक्टर ऑफिसर के परामर्श पर ईवीएम व वीवीपैट को सुरक्षित रखने के लिए उसे तृणमूल नेता के घर लेकर आए थे। सेक्टर ऑफिसर ने हालांकि स्वीकार किया कि उसने नियमों के विरुद्ध कार्य किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी कर वोट लूटने के इरादे से उन्हें तृणमूल नेता के घर लाया गया था। खबर पाकर राजपुर थाने की पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। सेक्टर ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने तंज कसते हुए कहा कि तृणमूल एक तरफ ईवीएम पर सवाल उठाती है और दूसरी तरफ उसे घर में रखती है। तृणमूल जानती है कि वह चुनाव में हार चुकी है इसलिए अब वह बदमाशी करके जीतने की कोशिश कर रही है। यह आज की बात नहीं है बल्कि उसकी पुरानी आदत है। पंचायत चुनाव के समय न्यूटाउन से भी वे लोग ईवीएम उठा ले गए थे और हुगली नदी में फेंक दिया था। ये सब घटनाएं चुनाव के समय घटती ही हैं। हमें इन सब चीजों को बदलने में वक्त लगेगा।
बता दें कि तीसरे चरण में तीन जिलों हावड़ा, हुगली और दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों पर कुल 205 प्रत्याशी मैदान में हैं। हावड़ा की सात, हुगली की आठ और दक्षिण 24 परगना जिले की 16 सीटें हैं। इन सभी सीटों को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है और धारा 144 लागू है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 31 सीटों में से 30 पर तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। तीसरे चरण में कुल 78,52,425 मतदाता 10,871 बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। केंद्रीय बलों की 618 कंपनियां तैनात हैं। सबसे ज्यादा 307 कंपनियां दक्षिण 24 परगना जिले में तैनात हैं। राज्य में 294 विधानसभा सीटों पर आठ चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण का मतदान 27 मार्च और दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल, 6 अप्रैल को यानी आज तीसरे चरण का मतदान, 10 अप्रैल को चौथे, 17 अप्रैल को पांचवें, 22 अप्रैल को छठे, 26 अप्रैल को सातवें और 29 अप्रैल को आठवें चरण का मतदान होगा। नतीजे दो मई को आएंगे।

पश्चिम बंगाल में हरिपाल विधानसभा सभा में राज्य विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान एक मतदान केंद्र के बाहर कतार में खड़े मतदाता ।

## तमिलनाडु चुनाव : वोटर लिस्ट से हटाया गया शशिकला का नाम, जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

**चेन्नई** । तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की विश्वस्त सहयोगी रही वी. के. शशिकला के वकील ने यहां सोमवार को कहा कि शशिकला का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है और यह अन्याय है. उन्होंने कहा कि शशिकला इसे लेकर दुखी हैं और इसके लिए जिम्मेदार रहे अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगीय एन. राजा संतूर पांडियन ने कहा कि तमिलनाडु में मंगलवार को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, चेन्नई की थाउजेंड लाइट्स विधानसभा सीट की मतदाता सूची से शशिकला का नाम हटा दिया गया है.
पांडियन ने एक तमिल टीवी चैनल से कहा कि अधिकारियों ने उन्हें बताया कि शशिकला का नाम 31 जनवरी 2019 को हटाया गया था, जब उस साल लोकसभा चुनाव होने वाले थे.
बताते चलें पिछले महीने ही शशिकला ने राजनीति से सन्यास लेने का फैसला किया था. चुनाव से ठीक एक महीने पहले उनके इस ऐलान से पार्टी को खासा झटका लगा था.
उन्होंने घोषणा की थी कि मैं राजनीति से दूर रहूंगी और अपनी बहन पुराचि थलावी (जयलिलता), जिन्हें मैं देवीतुल्य मानती हूं, और ईश्वर से अम्मा के स्वर्णयुगीन शासन की स्थापना के लिए प्रार्थना करती रहूंगी.
बता दें कि आज तमिलनाडु विधानसभा की सभी 234 सीटों पर मतदान हो रहा है. जहां 3,998 प्रत्याशियों की क़िस्मत का फैसला होगा. यह चुनाव तय करेगा कि क्या सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक की लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता में वापसी होगी या फिर एक दशक बाद द्रमुक सत्ता में लौटेगी.
इस चुनाव में मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, उपमुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम, द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन, एएमएमके संस्थापक टी टी वी दिनाकरण, अभिनेता एवं मक्कल नीधि मय्यम (एमएनएम) के संस्थापक कमल हासन, नाम तमीझार काच्ची के नेता सीमान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एल मुरूगन समेत 3998 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.

## महाराष्ट्र में कोरोनावायरस के 57 हजार से ज्यादा नए मामले, 222 मरीजों की मौत

**मुंबई** । महाराष्ट्र में कोरोनावायरस के 57,074 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान 222 लोगों की मौत हुई है. राज्य में संक्रमण के कुल मामले 30,10,597 हो गए. अब तक कुल 55,878 मरीजों की मौत हुई है. 25,22,823 लोग ठीक हो चुके हैं. राज्य में कोविड के 4,31,896 एक्टिव केस हैं. कोरोना मामलों में महाराष्ट्र के बाद केरल दूसरे स्थान पर है. वहां अब तक कुल 11,35,233 मामले सामने आ चुके हैं. इसके बाद कर्नाटक और चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश है.
महाराष्ट्र में सोमवार रात से लागू हुए लॉकडाउन के दायरे से पेट्रोल पंप, सरकारी एवं निजी सुरक्षा सेवाओं और फल विक्रेताओं को भी कड़े प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखते हुए इन्हें आवश्यक सेवाओं की सूची में जोड़ दिया गया है. संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार यह छूट दी गई है. हालांकि, सोमवार को जारी संशोधित आदेश में जिन प्रतिष्ठानों के कार्यालयों को संचालन की अनुमति दी गई है, उनके कर्मचारियों को जल्द से जल्द टीकाकरण कराना होगा.
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सप्ताहांत में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू करने की रविवार को घोषणा की थी. साथ ही 30 अप्रैल तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने की भी घोषणा की गई थी. ये सभी पाबंदियां सोमवार से राज्य में लागू हो गई. इसके अलावा कोरोनावायरस के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निजी कार्यालय, थियेटर और सैलून आदि बंद रखने जैसी कड़ी पाबंदियां भी लागू की गई हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में रविवार को कहा था कि सप्ताहांत में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा. इसके अलावा, सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी.
इस बीच, पुणे शहर में आवश्यक सेवाओं की दुकानों को छोड़कर 30 अप्रैल तक सभी प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे. पुणे नगर निगम ने सोमवार को जारी ताजा आदेश में यह पाबंदी लगाई है. आदेश के मुताबिक, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक एवं निजी बैंकों, बीमा एवं दूरसंचार कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के कार्यालय के अलावा बाकी सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे.
इसके मुताबिक, सप्ताहांत के लॉकडाउन के तहत शहर में शुक्रवार शाम छह बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि, इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी. पुणे के महापौर मुरलीधर मोहोल ने ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शहर की बाकी सभी दुकानें एवं बाजार 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे.

## एंटीलिया केस : कारों के बाद अब स्पोर्ट्स बाइक की एंट्री, केस में बाइक के रोल की जांच कर रही एनआईए

**मुंबई** । एंटीलिया केस में कारों के साथ अब एक स्पोर्ट्स बाइक की भी एंट्री हो गई है. मामले की जांच कर रही एजेंसी एनआईए ने स्पोर्ट्स बाइक को जब्त कर लिया है. एनआईए केस में अब इस बाइक के इस्तेमाल की जांच कर रही है. इसी बीच सचिन वझे की स्पोर्ट्स बाइक से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने की एक तस्वीर वायरल हुई है जो बताती है कि वझे को लग्जरी लक्जरी कारों के साथ स्पोर्ट्स बाइक चलाने का भी शौक था. लेकिन आतंकी साजिश की झूठी कहानी में बाइक की भूमिका पर अभी सवाल है.
वहीं, सोमवार रात एनआईए सचिन वझे को लेकर CST स्टेशन गई थी. जांच में पता चला है कि 4 मार्च की रात जब मनसुख गायब हुए थे तब वझे CST से लोकल गाड़ी पकड़कर ठाणे गया था. लेकिन अपना मोबाइल फोन मुम्बई पुलिस के अपने दफ्तर में ही छोड़ गया था ताकि अगर आगे कभी जांच हो तो उसका लोकेशन मुम्बई पुलिस दफ़्तर ही आये.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, बाइक सचिन वझे की एक कथित महिला सहयोगी के नाम पर पंजीकृत है. एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के अधिकारी बाइक को एक टेम्पो के जरिए दक्षिण मुंबई में अपने कार्यालय लेकर आए.
सूत्रों ने बताया कि कथित महिला सहयोगी से एनआईए ने शुक्रवार को पूछताछ की थी. जांच एजेंसी ने बृहस्पतिवार को मीरा रोड इलाके में एक फ्लैट की जांच की थी जिस पर महिला का कब्जा था. एनआईए को संदेह है कि 25 फरवरी को अंबानी के आवास 'एंटीलिया के पास एक एसयूवी मिलने के पहले, महिला 16 फरवरी को वझे के साथ शहर के एक होटल में गयी थी.
एनआईए ने पूर्व में वझे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आठ महंगी गाड़ियां जब्त की थीं. वझे को मामले में पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था.

## मुंबई सीआरपीफ मुख्यालय में आये ईमेल से हडकंप, गृहमंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा; मल्टीपल बम ब्लास्ट की धमकी

**मुंबई** । मुंबई में सीआरपीफ मुख्यालय को एक धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ है। इस ई-मेल के आने से हडकंप मच गया है। इसमें लिखा गया है कि देश के गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा है। इसके साथ ही इस ई-मेल में सार्वजनिक जगहों, मंदिरों और एयरपोर्ट पर मल्टीपल बम ब्लास्ट करने की धमकी भी दी गई है। बता दें कि ये ई-मेल चार से पांच दिन पहले मिला है। सीआरपीएफ के थ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिये इस ई-मेल को एनआईए समेत खुफिया एजेंसियों को जांच के लिए सौंप दिया गया है। देश की तमाम बड़ी एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हुई हैं।

मुंबई मुख्यालय में आये धमकी भरे ई मेल के बाद से ही तमाम खुफिया एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। ये एजेंसियां ईमेल सोर्स और ईमेल लिखने वाले का पता लगा रही हैं। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर माह में एनआइए कंट्रोल रूम में भी इसी तरह का एक कॉल रिसीव किया गया था। जांच में पता चला था कि कॉल करने वाला पाकिस्तान के कराची शहर का था। इस कॉल में मुंबई पोर्ट और पुलिस स्टेटमेंट पर जैश के हमले के प्लान के बारे में बताया गया था। हालांकि इस मामले की जांच अभी भी जारी है।
गृहमंत्री अमित शाह को गणतंत्र दिवस पर बम से उड़ाने की धमकी भरा एक पत्र मिला था। इनके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरधना विधायक संगीत सोम समेत कई देश के कई वरिष्ठ नेताओं को मारने की बात भी इस पत्र में कही गई थी। जनवरी में इसी साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। हालांकि जांच के बाद आरोपी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। सीएम योगी पहले से ही आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। जिसके चलते उन्हें भी मिली हुई है।

## राजसमंद जिले में अपने हिस्से की जमीन बेचने से रोका तो छोटे ने करा दी बड़े भाई की हत्या

**उदयपुर** । राजसमंद जिले के परमारों की भागल बड़गांव में तीन दिन पहले कुएं में उतराते शव को लेकर चौकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस की जांच में पता चला कि उसकी हत्या की गई और उसके छोटे भाई ने सुपारी देकर उसकी हत्या कराई। इस मामले में पुलिस ने छोटे भाई, उसकी पत्नी सहित छह जनों को गिरफ्तार किया है।
मिली जानकारी के अनुसार तीन दिन पहले परमारों की भागल बड़गांव के एक खेत के कुएं में उदयलाल भील का शव उतराता मिला। पुलिस पहले इसे सामान्य घटना मानकर चल रही थी लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मौत से पहले उसके साथ मारपीट की गई थी तथा उसके सिर तथा चेहरे पर चोट के निशान मिले थे। जिस पर पुलिस को उसकी हत्या की आशंका हुई और इसी नजरिए से जांच में जुटी हुई थी। इस बीच पुलिस को पता चला कि मृतक उदयलाल का छोटा भाई हीरासिंह बैंक के कर्ज के चुकारे के लिए पैतृक भूमि में से अपने हिस्से को बेचना चाह रहा था लेकिन बड़ा भाई उदयलाल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जिस पर उसने अपनी पत्नी और उसके परिचितों के साथ मिलकर अपने बड़े भाई की हत्या की साजिश रची और दो लाख में सुपारी दे दी।
थानाधिकारी शैतानसिंह ने बताया कि उदयलाल की हत्या के मामले में परमारों की नीचली भागल बड़गांव केलवाड़ा निवासी उसके छोटे भाई हीरासिंह पुत्र मोतीसिंह, उसकी पत्नी नाथीबाई, रुपी टांकड़ी बड़गांव निवासी किशनलाल पुत्र कुराजी भील, मेफावतों का वास समीचा निवासी प्रेमसिंह पुत्र मदनसिंह, बड़गांव निवासी भैरूलाल पुत्र पेमाराम भील और नाथा की बस्ती बड़गांव निवासी नारुलाल पुत्र लालराम भील को गिरफ्तार कर लिया।
पता चला कि मोतीसिंह एवं नाथीबाई ने नारू भील को उदयलाल की हत्या के लिए दो लाख रुपए की सुपारी दी थी लेकिन नारू ने इस काम में अपने दोस्त किशनलाल, प्रेमसिंह व भैरूलाल को भी शामिल कर लिया था। हत्या से पहले सभी आरोपियों ने उदयलाल के साथ शराब पी तथा नशा गहराने पर नारू ने उदयलाल पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जबकि उसके सहयोगी किशनलाल, प्रेमसिंह तथा भैरूलाल ने उदयलाल पर लाठी से हमला किया। उसके अचेत होने पर वह उसे घसीटकर ले गए तथा कुएं में फैंक गए। घटना के समय उदयलाल जिंदा था। बताया गया कि उदयलाल और उसके भाई के पास तीस बीघा पैतृक कृषि भूमि थी, जिसमें से पंद्रह बीघा भूमि छोटा भाई हीरालाल बेचना चाह रहा था।

## सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं बाहुबली मुख्तार अंसारी की बीवी, फेक एनकाउंटर होने का जताया डर

**नई दिल्ली** । बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की पत्नी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं. उन्होंने अदालत से मुख्तार अंसारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है. उन्होंने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी ने अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल ट्रांसफर करने के दौरान और कोर्ट में पेशी समेत अन्य मौकों पर सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश देने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि अंसारी की जान को खतरा है.
उनके जीवन के लिए आसन्न खतरे का हवाला देते हुए (बीजेपी के खिलाफ सफलतापूर्वक चुनाव लड़ने और यूपी में बीजेपी के सदस्यों के खिलाफ मामलों के गवाह होने के कारण), अंसारी की पत्नी ने प्रार्थना की है कि संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाए कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिले और इस प्रक्रिया के दौरान उनका एनकाउंटर ना किया जाए.
याचिका में अंसारी को खत्म करने के विभिन्न प्रयासों का विवरण दिया गया है और विभिन्न खतरों को उजागर किया गया है. यह आगे बताया गया है कि माफिया डॉन बृजेश सिंह जो कि यूपी में सरकार का हिस्सा है और बेहद प्रभावशाली है, उसे राज्य की सहायता और समर्थन के साथ मारने की साजिश रच रहा है.
याचिका में उत्तर प्रदेश पुलिस के पिछले आचरण का हवाला दिया है और यूपी पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ों के उदाहरण दिए गए हैं. याचिका में प्रार्थना की गई है कि उनके पति के साथ ऐसा ना हो, कहीं उनका विकास सिंह मुठभेड़ वाला हाल न हो.
बता दें कि मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों पंजाब से यूपी की बांदा जेल ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे. कोर्ट के आदेश पर पंजाब पुलिस मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को सौंपेगी. करीब दो साल से मुख्तार को पंजाब पुलिस वहां के एक रंगदारी मांगने के मामले में यूपी से पंजाब ले गई थी, तब से मुख्तार सेहत खराब होने के नाम पर पंजाब जेल में बंद है. इस मामले में लंबे समय से यूपी और पंजाब सरकार के बीच तनातनी चल रही है. इस बीच यूपी सरकार मुख्तार अंसारी को पंजाब से 13 बार लाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुई.

## राजस्थान में कोरोना संक्रमण खतरनाक स्थिति में पहुंचा, नियम तोड़ने वाले पर होगी सख्ती

**जयपुर** । राजस्थान में कोरोना संक्रमण खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। यहां पिछले दो माह की तुलना में अप्रैल माह में संक्रमण की रफ्तार करीब 1.50 फीसदी बढ़ी है। संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर निगाह रखने के लिए पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमों का गठन किया है। सरकार ने तय किया है कि अब यदि किसी संक्रमित ने होम क्वारंटीन के नियम तोड़े तो उसे सरकारी सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा।
चिकित्सा विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश में 1.13 प्रतिशत आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। एक सप्ताह बाद सरकार ने प्रतिदिन 7 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। पुलिस ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 12 लाख 29 हजार लोगों के चालान किए हैं। इनमें सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने मिसाइल पर 3 लाख 76 हजार, बिना मास्क पहले लोगों को सामान बेचने वाले दुकानदारों पर 15 हजार 27, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ 8 लाख 31 हजार 100 चालान किए गए हैं।
पुलिस महानिदेशक एम.एल.लाठर ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर थूंकने, शराब का सेवन करने, क्वारंटीन के तय नियमों का सही पालन नहीं करने पर 3 हजार 926 मामले दर्ज कर 10 हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। निषेधाज्ञा तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 लाख 45 हजार 58 वाहनों का चालान किया गया है। वहीं 2 लाख से ज्यादा वाहन जब्त किए गए । इन लोगों से 36 करोड़ 15 लाख का जुर्माना वसूलला गया है । इसी तरह सोशल मीडिया का दुरूपयोग करने पर 272 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ।
उधर, प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 35 से 36 हजार कारोना जांच हो रही है। प्रदेश में अब तक कुल तीन लाख 39 हजार से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी में जहां एक दिन में 60 संक्रमित थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 2000 प्रतिदिन तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो गया उन्हें भी दो गज की दूरी और मास्क के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। केंद्र सरकार को वैक्सीनेशन सभी के लिए मुहैया करानी चाहिए, इसमें उम्र की सीमा हटानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में मृत्युदर 0.84 प्रतिशत है, जबकि 96.3 प्रतिशत लोग रिकवर होकर घर जा रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य रूप से 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं हो। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें 14 दिन के होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। यदि वे होम आइसोलेशन में प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। प्रदेश में रविवार को कोरोना के 1729 पॉजिटिव मामले आए। हमारी क्षमता प्रतिदिन 70,000 टेस्ट करने की है, इसे बढ़ाकर एक लाख करेंगे।
राजस्थान में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजक पार्क, स्वीमिंग पूल और जिम आगामी आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ की स्कूलों में एक से नौ तक की कक्षाओं का संचालन नहीं होगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद हॉल में होने की दशा में कुल क्षमता का 50 फीसद और अधिकत 100 व खुले ग्राउंड में रखने पर प्रत्येक दो लोगों के बीच दो गज की दूरी तय करना जरूरी होगा। गृह विभाग की ओर से रविवार रात जारी गाइडलाइन के अनुसार, रेस्टोरेंट को अब कर्फ्यू में छूट नहीं रहेगी, ये रात नौ बजे बंद हो जाएगी। वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में जरूरत के अनुसार 75 फीसद कर्मचारियों को बुलाया जा सकेगा। शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम की स्थिति में रहेंगे।

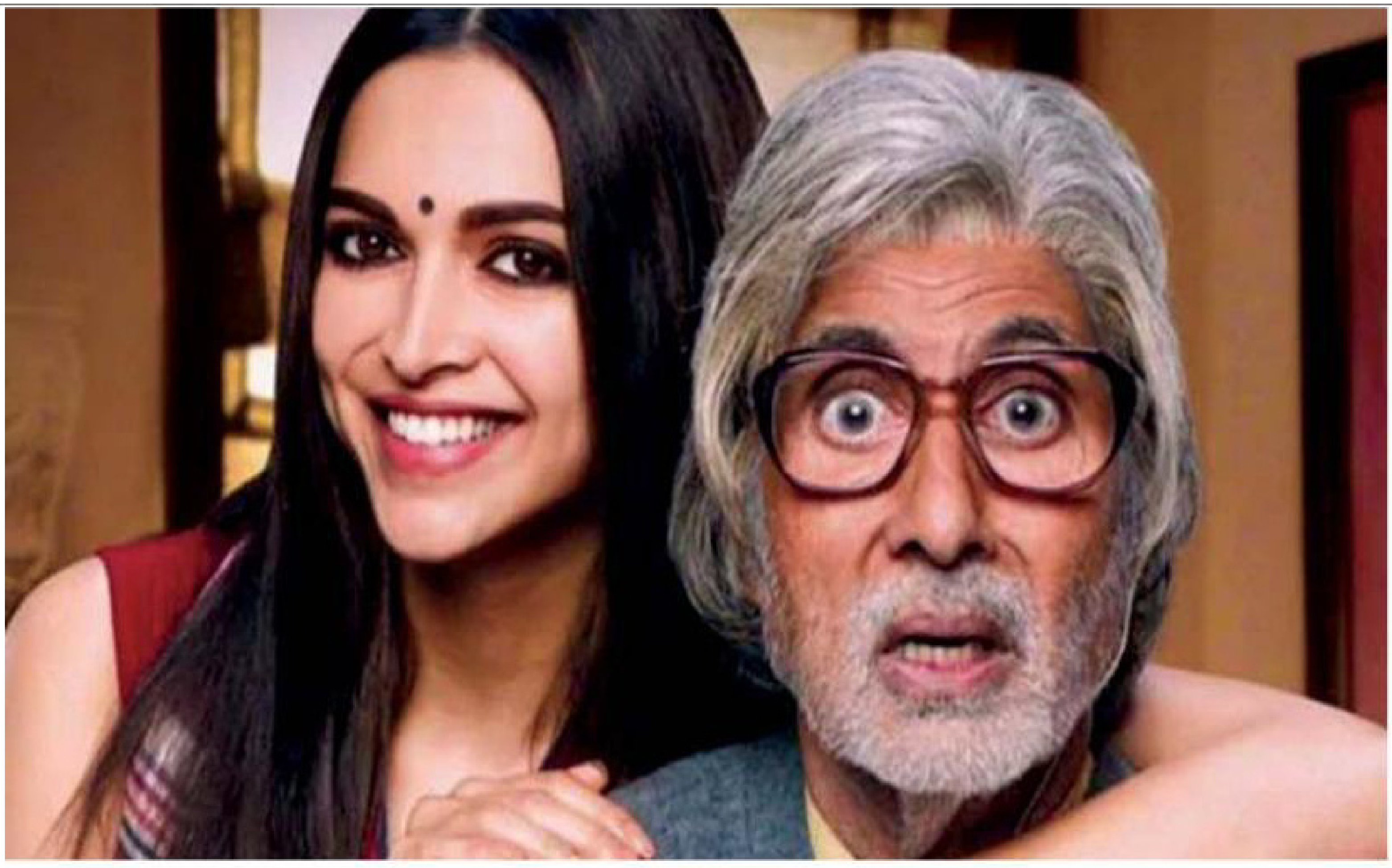

# पीकू के बाद फिर साथ काम करेंगे दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन

**दीपिका पादुकोण** और अमिताभ बच्चन हॉलीवुड फिल्म, द इंटर्न के भारतीय रूपांतरण के लिए फिर से एक साथ काम करने के लिए तैयार है। रीमेक का निर्देशन अमित रविन्द्रनाथ शर्मा द्वारा किया जाएगा और सुनीर खेतरपाल और दीपिका द्वारा निर्मित किया जाएगा। दीपिका ने फिल्म की घोषणा करने के लिए इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर साझा किया। उन्होंने  लिखा, 'मेरे सबसे खास सह-कलाकार के साथ फिर से सहयोग करने के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। द इंटर्न हॉलीवुड की 2015 में आयी एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट डी नीरो और ऐनी हैथवे ने प्रमुख भूमिकाओं में अभिनय किया था। फिल्म नैन्सी मेयर्स द्वारा लिखित और निर्मित की गई थी। यह फिल्म एक 70 वर्षीय व्यक्ति (डी नीरो) की कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ऑनलाइन फैशन वेबसाइट पर सीनियर इंटर्न बन जाता है। ऐनी हैथवे, जो कंपनी के सीईओ की भूमिका निभाते हैं, डी नीरो के चरित्र के साथ एक अप्रत्याशित दोस्ती बनाती है। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली थी। आपको बता दें कि बिग बी और दीपिका पादुकोण  ने शूजीत सरकार की 2015 में आयी  फिल्म पीकू में साथ काम किया था। अभिताभ बच्चन ने फिल्म में एक पिता की भूमिका निभाई थी और बेटी की भूमिका में दीपिका नजर आयी थी। उनकी बॉन्डिंग को आलोचकों और दर्शकों ने काफी सराहा।

## सनी लियोनी ने जब सनी देओल से मांगी थी माफी

**सनी देओल** और सनी लियोनी में एक ही बात कॉमन है कि दोनों का नाम सनी है। इसलिए चुटकुला बन गया था कि दोनों यदि शादी कर लें तो दोनों का ही नाम सनी देओल होगा। इसके अलावा भी कई ऐसे चुटकुले बने जो घटिया चुटकलों की श्रेणी में आते हैं। यह बात सनी लियोनी तक पहुंची और सनी देओल तक भी। जाहिर सी बात है कि दोनों को ही बुरा लगा होगा। जब सनी लियोनी की फिल्म 'मस्तीज़ादे' रिलीज होने वाली थी तो सनी लियोनी प्रमोशन में लगी हुई थीं। उस दौरान सनी लियोनी ने सनी देओल से माफी मांगते हुए कहा कि दोनों का फर्स्ट नेम कॉमन होने के कारण कई घटिया जोक्स बने हैं। सनी कहती हैं 'आई एम सॉरी सनी देओल। मुझे माफ कर दो। हमारे ऊपर कई घटिया जोक्स बने हैं जिसकी जवाबदार मैं हूं।' वैसे इसमें सनी की कोई गलती नहीं है, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ कर माफी मांगी है। उम्मीद है कि सनी देओल भी इन जोक्स के लिए सनी लियोन को जवाबदार नहीं मानते होंगे।

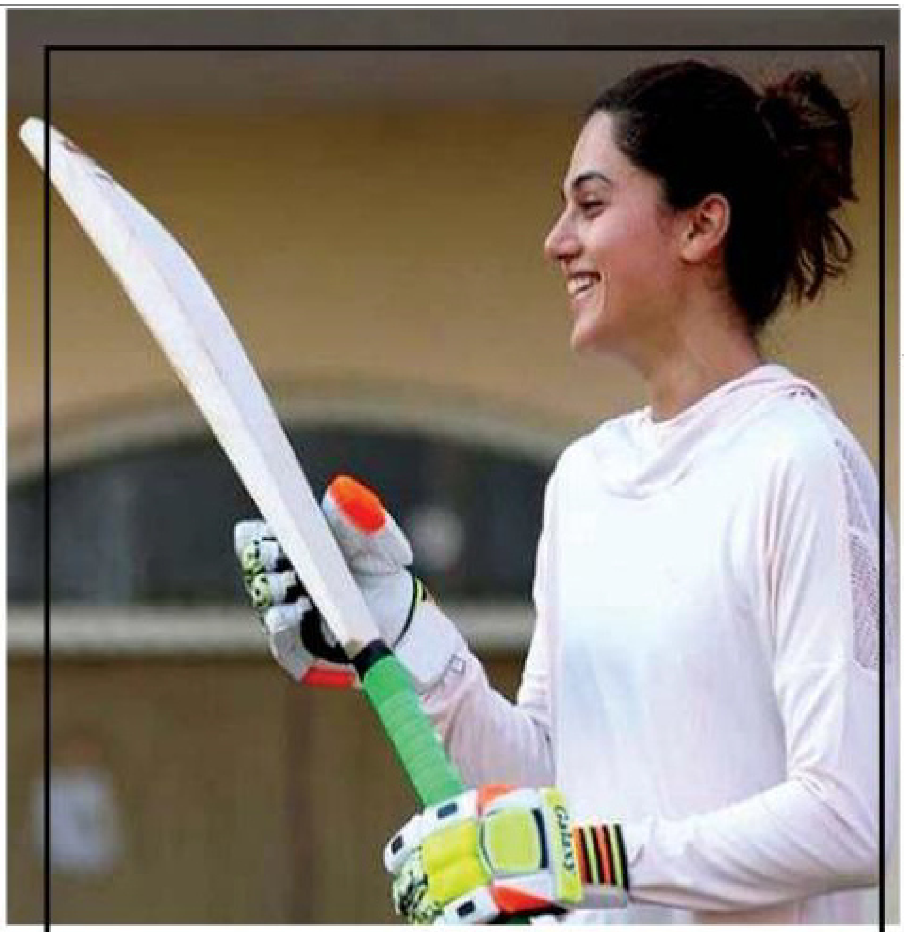

# तापसी पन्नू ने शुरू की 'शाबाश मिट्ठू' की शूटिंग

**बॉलीवुड** एक्ट्रेस तापसी पन्नू के पास इन दिनों कई फिल्मों की लाइन लगी हुई हैं। इन्हीं में एक है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज की बायोपिक 'शाबाश मिट्ठू' भी है। इस फिल्म के लिए तापसी पन्नू जमकर मेहनत कर रही हैं।  खबर है कि तापसी ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट कर प्रशंसकों को ये जानकारी दी है। शूट के पहले दिन अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए तापसी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'चलिए शुरू करते हैं। पहला दिन, शाबाश मिट्ठू...।' तापसी ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें वह हाथ में बैट पकड़े और हेलमेट लगाए नजर आ रही हैं। फैंस को उनका यह क्रिकेटर वाला अवतार बेहद पसंद आ रहा है। तापसी को देख तो ऐसा ही लग रहा है कि वह क्रिकेटर की भूमिका के साथ इंसाफ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तापसी पन्नू इस रोल के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। मिताली राज की दोस्त और पूर्व क्रिकेटर नूशिन अल खादिर तापसी को कोचिंग दे रही हैं। तापसी पन्नू ने कहा था, मैंने पहले कभी क्रिकेट नहीं खेला है, वह बस इस गेम की फैन रही हूं। यह भूमिका एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि दबाव मुझे सबसे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। 'शाबाश मिट्ठू' की बात करें तो इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया कर रहे हैं और इस फिल्म को प्रिया अवन ने लिखा है। फिल्म का निर्माण वायकॉम 18 स्टूडियो कर रहा है। मिताली भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। उनकी कप्तानी में भारत साल 2017 में वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था।  तापसी पन्नू के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म लूप लपेटा की शूटिंग खत्म की है। वह इसके अलावा रश्मि रॉकेट में नजर आने वाली हैं। तापसी फिलम 'दोबारा' और 'हसीन दिलरूबा' में भी दिखेंगी।

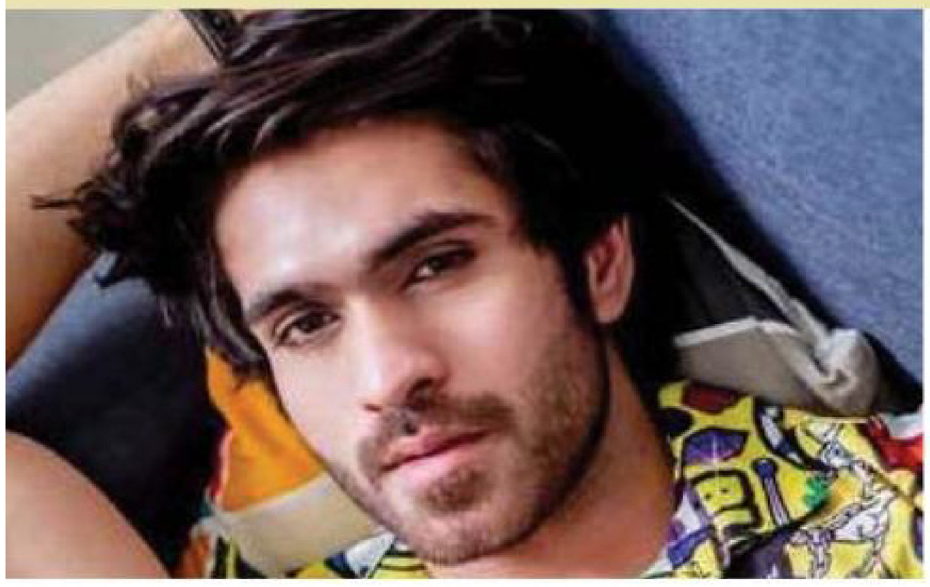

# जब मैं इस शहर में आया तो मुझे मुंबई का 'एम' भी नहीं पता था

**जी टीवी** ने हाल ही में अपना नया शो 'तेरी मेरी इक्क जिन्दड़ी' शुरू किया है, जो विपरीत स्वभाव के दो लोगों माही और जोगी की एक अनोखी प्रेम कहानी है, जिनके व्यक्तित्व और जिंदगी के प्रति दोनों का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है, लेकिन फिर भी वो प्यार के एक ही रास्ते पर चल पड़ते हैं। इस शो में एक्ट्रेस अमनदीप सिद्धू, माही किरदार निभा रही हैं, और उनके अपोजिट पॉपुलर एक्ट अध्विक महाजन, जोगी के रोल में हैं। इसके अलावा मनीष वर्मा भी गुलशन का किरदार निभा रहे हैं जिसे दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। गुलशन एक कॉलेज बॉय है, जो दिखने में आकर्षक है। वो जोगी और माही की जिंदगी में हलचल मचाने में लगा रहता है। यह एक्टर इस शो में जबरदस्त स्टाइल लेकर आए, जिससे इसमें दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ गई है। एक्टिंग हमेशा से मनीष का सपना रहा है, लेकिन इस सपने की जड़ में उनके पिता का सपना भी शामिल है। दरअसल, उनके पिता भी यही चाहते थे कि मनीष एक एक्टर बनें। मनीष ने अपने कॉलेज के दिनों में एक्टिंग में अपना किस्मत आजमाना शुरू किया। मनीष दिल्ली से हैं और इसलिए उन्हें मुंबई के बारें में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन उन्होंने इस बात को अपने सपनों के बीच रुकावट नहीं बनने दिया। बाकी लोगों से अलग उनका संघर्ष हर दिन बेहतर करने और एक एक्टर के रूप में खुद को साबित करने की अपनी उम्मीदों और इच्छाओं से था। मनीष बताते हैं, जब मैं इस शहर में आया था, तो मुझे मुंबई का 'एम' भी नहीं पता था। अपने सपने के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, एक्टिंग हमेशा से मेरे दिमाग में थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि मुझे पता नहीं था कि कहां से शुरुआत की जाए। मुझे लगा कि मॉडलिंग के जरिए आप संपर्क बना सकते हैं और फिर एक्टिंग में आ सकते हैं।

# मेरे लिए 'क्राइम पैट्रोल' एक मशाल की रोशनी की तरह है : सोनाली कुलकर्णी

**कई** हिंदी और मराठी फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी अब क्राइम पैट्रोल सतर्क की यूनीक सीरीज होस्ट करने के लिए तैयार हैं। जस्टिस रीलोडेड नाम से शुरू होने वाले शो के इस नए एडिशन में नाटकीय अंदाज में ऐसे जघन्य अपराधों की दास्तां बयां की जाएगी जो कई चुनौतियों के चलते अनसुलझे रहे और उनको सुलझाने के लिए नए सिरे से सोचना पड़ा। बतौर होस्ट, सोनाली कुलकर्णी इन एपिसोड के माध्यम से दर्शकों को चेताने के साथ-साथ सोच में किए जाने वाले जरूरी बदलावों के बारे में भी बताएंगी जो कि सिर्फ मुश्किल ही नहीं, भड़काने वाले भी हैं। एपिसोड के माध्यम से वे किसी भी क्राइम के खिलाफ किए जाने वाले केस के महत्व के बारे में भी लोगों को जागरुक करेंगी।

### लोगों को सतर्क करना चाहती हूं

अपने नए किरदार के बारे में सोनाली कुलकर्णी ने कहा, 'मैंने हाल ही में 'क्राइम पेट्रोल' की टीम के साथ काम करना शुरू किया है। ये टीम बहुत ही शानदार है। इतनी परफेक्ट और जोश से भरपूर टीम के साथ काम करने से एक कलाकार का काम भी बेहतरीन हो जाता है। मेरे लिए 'क्राइम पैट्रोल' एक मशाल की रोशनी की तरह है जो हमें सतर्क करती है और मैं टीम के लिए उस मशाल को पकड़कर लोगों को सतर्क करना चाहती हूं और कहना चाहती हूं कि जुर्म के जाल में फंसने से बेहतर है कि हम समझदार और जिम्मेदार बन जाएं।

### अनूप को गर्व करनेका मौका दूंगी

आगे उन्होंने बताया, मैंने अनूप का काम देखा है और वह जो भी करते हैं उससे दर्शकों में उत्सुकता पैदा होती है, चाहे वह सीरीज हो या टीवी शो। तो क्राइम पेट्रोल और अनूप दोनों का ही मेरे लिए स्ट्रांग एसोसिएशन है, और जिस तरह उन्होंने दर्शकों के दिल में अपने प्रति विश्वास जताया है वह मेरे लिए बहुत खास है। मैं बतौर एक्टर और बतौर दोस्त उन पर गर्व करती हूं। जहां तक रही बात क्राइम पेट्रोल के सीजन की तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें गर्व महसूस करने का मौका दूंगी। यह मौका मुझे राकेश सारंग की तरफ से मिला और मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने एंकर के तौर पर मेरे नाम पर विचार किया।

# आईपीएल पर कोरोना का साया

## मुंबई स्टेडियम में 3 स्टाफ पॉजिटिव, सीएसके समेत 4 टीमें कर रहीं प्रैक्टिस; अब तक 3 खिलाड़ी समेत 23 लोग संक्रमित

**मुंबई।** इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का आगाज 9 अप्रैल से होना है। इससे पहले ही टूर्नामेंट पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मंगलवार को 2 ग्राउंड स्टाफ और एक प्लंबर संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले स्टेडियम के 10 स्टाफ मेंबर और 6 इवेंट मैनेजर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी।

वानखेड़े में 4 टीमों ने अपना कैंप लगाया हुआ है। यह टीमें दिल्ली कैपिटल्स , चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स हैं। ओवरऑल अब तक टूर्नामेंट में 3 खिलाड़ी समेत 23 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं।

**3 खिलाड़ी संक्रमित हो चुके**

यह 3 प्लेयर कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज नीतीश राणा, दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर अक्षर पटेल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ओपनर देवदत्त पडिक्कल हैं। राणा और पडिक्कल की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। अक्षर की अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी। इनके अलावा CSK की कंटेंट टीम का एक सदस्य भी संक्रमित पाया गया था। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सभी स्टाफ को वानखेड़े स्टेडियम के पास एक क्लब हाउस में ठहराया गया है। सभी को यात्रा करने और स्टेडियम एरिया से बाहर निकलने की अनुमति भी नहीं है।

**मुंबई में 10 से 25 अप्रैल के बीच 10 मैच होंगे**

लीग स्टेज के 56 में से चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु में 10-10 मैच खेले जाएंगे। जबकि दिल्ली और अहमदाबाद में 8-8 मैच होंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह सभी मैच 10 से 25 अप्रैल के बीच होंगे। पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 10 अप्रैल को खेला जाएगा। प्ले-ऑफ और फाइनल अहमदाबाद में होंगे।

**महाराष्ट्र में हर वीकेंड पर लॉकडाउन, लेकिन IPL होगा**

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में 9 अप्रैल को शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक हर वीकेंड पर लॉकडाउन रहेगा। हालांकि, ऐसे में IPL के दौरान मुंबई में मैच होने पर भी टीम को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि राज्य सरकार ने IPL को मंजूरी दे दी है। मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शक नहीं रहेंगे। टीम को रात 8 बजे के बाद भी प्रैक्टिस और होटल तक आने-जाने की अनुमति दी गई है।

**मुंबई से शिफ्ट हो सकते हैं मैच, इंदौर-हैदराबाद स्टेंडबाय**

सूत्रों की मानें तो मुंबई में कोरोना के मामले बढ़े तो सभी मैचों को शिफ्ट किया जा सकता है। इसके लिए इंदौर और हैदराबाद को स्टेंडबाय के तौर पर रखा गया है। वहीं, BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए BCCI ने सुरक्षा के सभी इंतजाम पहले से ही कर रखे हैं। यही कारण है कि सिर्फ 6 वेन्यू चुने गए, जहां बायो-बबल तैयार किया गया। राजीव ने बिना किसी परेशानी के टूर्नामेंट सफलता पूर्वक होने की उम्मीद जताई है।

**खिलाड़ियों को वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी: राजीव**

राजीव ने कहा कि लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों से निपटने का एक ही तरीका है। यह वैक्सीन है। BCCI भी यही मानती है कि खिलाड़ियों को वैक्सीन लगानी चाहिए। कोई नहीं जानता कि कोरोनावायरस कब खत्म होगा और न ही कोई इस वायरस के अंत होने की तारीख बता सकता है। ऐसे में खिलाड़ियों के लिए खेलना आसान नहीं होगा। मेरा मानना है कि अब हमें इस बारे (वैक्सीन लगवाने) में सोचना होगा। खिलाड़ियों को भी लगाना बेहद जरूरी है।

BCCI उपाध्यक्ष से पूछा गया कि खिलाड़ियों को वैक्सीन लगवाने के लिए बोर्ड ने स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखित आवेदन दिया है क्या? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि BCCI ने यह सुझाव दिया और अपनी बात रखी है। हालांकि, खिलाड़ियों को वैक्सीन लगवाने के लिए BCCI लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में बना हुआ है।

## मैरीकॉम करेंगी भारतीय दल की अगुवाई, दिल्ली कर रहा एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी

**नई दिल्ली।** छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम अगले माह होने वाली एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेंगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में होने वाला यह टूर्नामेंट 21 से 31 मई तक चलेगा।

बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नॉन ओलंपिक भार वर्ग में बीते हफ्ते राष्ट्रीय ट्रायल्स किए थे। एमसी मैरीकॉम के अलावा सिमरनजीत कौर (60 किग्रा), लोविना बोरगोहेन (69 किग्रा) और पूजा रानी (75 किग्रा) तीन ऐसी महिला मुक्केबाज हैं, जिन्होंने ट्रायल्स में भाग नहीं लिया, लेकिन टूर्नामेंट खेलेंगी। चैंपियनशिप का आयोजन बीते साल नवंबर-दिसंबर में एक ही स्थान पर होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। वर्ष 2019 से पहले एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप को पुरुषों और महिलाओं के लिए दो व्यक्तिगत कार्यक्रमों के रूप में आयोजित किया गया था। भारत ने आखिरी बार पुरुषों का कार्यक्रम 1980 में मुंबई में आयोजित किया था।

## कड़े मुकाबले में भारतीय महिला फुटबॉल टीम उज्बेकिस्तान से हारी

**नई दिल्ली।** भारतीय महिला फुटबॉल टीम को उज्बेकिस्तान के खिलाफ मैत्री मैच में 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। दोनों ही टीमों को कई मौके मिले लेकिन उज्बेकिस्तान ने 87वें मिनट में मुफ्तना शोइमोवा की मदद से मैच का निर्णायक गोल कर दिया। कड़ी ठंड के बीच हुए मुकाबले में भारतीय कप्तान अदिति चौहान ने मैच के शुरू में कुछ अच्छे प्रयास किए। इसी तरह रंजना चानू और मिडफील्डर संगीता ने बाएं छोर से हलचलें बनाईं लेकिन उज्बेकिस्तान की मजबूत रक्षक पंक्ति ने मेहमान टीम के गोल करने के मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया। भारत की रक्षा पंक्ति में स्वीटी देवी ने मेजबान टीम के कई हमले निष्फल किए। मध्यांतर से पहले उज्बेकिस्तान को मौका मिला था लेकिन नीलूफर का प्रयास गोलपोस्ट से टकराकर रह गया। दूसरे हाफ में उतरी दया देवी ने सौम्या के साथ मिलकर विपक्षी टीम की रक्षक पंक्ति को परेशान किया था। दूसरे मैच में भारतीय टीम का सामना बेलारूस से होगा।

## लाहिड़ी का 1260 दिनों के बाद अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन, टेक्सास ओपन में पांचवें स्थान पर रहे

**मुंबई।** भारतीय गोल्फर अनिर्बान लाहिड़ी लगातार तीसरी बार तीन अंडर 69 के स्कोर से यहां चल रहे वालेरो टेक्सास ओपन में पांचवें स्थान पर रहे जो अक्तूबर 2017 के बाद उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन से लाहिड़ी को इनामी राशि के तौर पर 3,15,700 डॉलर (लगभग 2.31 करोड़ रुपये) मिले। पहले दौर में एक अंडर-71 का कार्ड खेलने वाले लाहिड़ी ने दूसरे, तीसरे और चौथे दौर में एक समान तीन अंडर 69 का कार्ड खेला। वह कुल 10 अंडर के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहे। इससे पहले अक्तूबर 2017 में सीजे कप नाईन ब्रिजेज में वह शीर्ष पांच गोल्फरों में शामिल थे। हीरो इंडियन ओपन 2015 में अपना आखिरी खिताब जीतने वाले लाहिड़ी ने 1260 दिनों के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया तो वही अमेरिका के जोर्डन स्पीथ 1351 दिनों के बाद चैंपियन बने। इससे पहले 2017 में रॉयल बिर्कडाले में चैंपियन बनने वाले इस गोल्फर ने आखिरी दौर में छह अंडर का कार्ड खेल कुल 18 अंडर के स्कोर के साथ खिताब अपने नाम किया। चार्ली हॉफमैन (16 अंडर) दूसरे और मैट वालेस (14 अंडर) तीसरे स्थान पर रहे।

**रैंकिंग में भी सुधार:**

लाहिड़ी ने इसके साथ ही 110 फेड एक्स कप अंक हासिल किए जिससे वह तालिका में 125वें से 94वें स्थान पर पहुंच गए। लाहिड़ी विश्व रैंकिंग में बड़ी सुधार करते हुए 478वें से 319वें स्थान पर पहुंच गए। वह रैंकिंग में दूसरे सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी हैं और दो-तीन अच्छे प्रदर्शन से उन्हें दूसरी बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व का मौका मिल सकता है। उन्होंने कहा, 'मैं मेहनत और लगन से काम कर रहा हूं। मैंने अपना ध्यान सिर्फ बेहतर होने पर दिया है और वास्तव में परिणामों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। लेकिन कुछ परिणाम बहुत अच्छे नहीं थे।'

## आईपीएल में भ्रष्टाचार रोकेंगे नए एसीयू चीफ

### शाबिर हुसैन ने कहा- सरकार ने सट्टेबाजी पर बैन लगाकर सही किया, इसे लीगल करने से मैच फिक्सिंग का खतरा है

**नई दिल्ली।** भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शाबिर हुसैन शेखदम खांडवावाला को एंटी-करप्शन यूनिट का नया चीफ नियुक्त किया है। शाबिर अब IPL समेत भारतीय क्रिकेट में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम करेंगे। उनका मानना है कि सरकार ने क्रिकेट में सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाकर सही किया है। सट्टेबाजी को लीगल करने से मैच फिक्सिंग बढ़ सकती है।

कई लोगों का मानना है कि सट्टेबाजी को लीगल करने से सरकार को राजस्व में भारी कमाई होगी। हालांकि, शाबीर ऐसा मानना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सट्टेबाजी को लीगल करती है या नहीं, यह अलग बात है। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरा मानना है कि सट्टेबाजी को लीगल करने से मैच फिक्सिंग का खतरा है। फिलहाल, इस पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का फैसला सही है।

**नियमों को सख्त बनाने का काम करेंगे: शाबिर**

शाबिर गुजरात के पूर्व DGP हैं। उन्होंने कहा कि सट्टेबाजी से मैच फिक्सिंग को बढ़ावा मिलता है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। हमें नियमों को और भी सख्त बनाने की जरूरत है। इसको लेकर भी हम काम करेंगे। आज क्रिकेट बड़े पैमाने पर बिना भ्रष्टाचार के कराया जा रहा है। इसका सारा श्रेय BCCI को जाना चाहिए।

**पूर्व चीफ और अनुराग सट्टेबाजी को लीगल करने के पक्ष में**

पूर्व चीफ अजीत सिंह का कुछ अलग ही मानना है। उनके मुताबिक, सट्टेबाजी को लीगल करना भी खेल में भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने का एक तरीका ही है। वहीं, BCCI के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी सट्टेबाजी को लीगल करने के पक्ष में हैं। उन्होंने पिछले साल इसका सुझाव भी दिया था।

**फैंस के भरोसे को बनाए रखना होगा: शाबिर**

शाबिर ने कहा कि कुछ देशों में सट्टेबाजी लीगल हो सकती है, लेकिन वे लोग जो स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं या टीवी पर देखते हैं, उनके साथ यह धोखाधड़ी होगी। क्योंकि वे यह मानते हैं कि खेल ईमानदारी से चल रहा है। फैंस मैच फिक्सिंग की सोचकर स्टेडियम में नहीं जाते। हमें उनके विश्वास को बनाए रखना होगा और खेल को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना होगा।

**छोटे टूर्नामेंट्स से भ्रष्टाचार खत्म करना होगा**

पूर्व छत्रक्ष ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों को खेल में मोटी रकम मिलते है। यही कारण है कि वे मैच फिक्सिंग जैसी गंदगी से काफी दूर हैं। इस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती छोटे टूर्नामेंट और लीग से भ्रष्टाचार को खत्म करना है। हमें खेल में हर तरह की आशंका को खत्म करना होगा और मैच पूरी तरह भ्रष्टाचार से मुक्त रखना होगा।

## महाराष्ट्र सरकार का फैसला, वानखेड़े में आईपीएल टीमों को रात 8 बजे के बाद प्रैक्टिस की इजाजत

**मुंबई।** इंडियन प्रीमियर लीग को शुरू होने अब महज कुछ दिन ही रह गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड से बुरी तरह प्रभावित मुंबई में आइपीएल मैचों के आयोजन का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार ने महामारी रोकने के लिए लगाए गए रात के कर्फ्यू के दौरान रात आठ बजे के बाद अभ्यास करने और टीमों को होटल तक आने की अनुमति दे दी। मुंबई और महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण राज्य सरकार ने रविवार को मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी। इन दिशानिर्देशों का पालन सोमवार से किया जा रहा है। राज्य सरकार ने हालांकि आइपीएल टीमों को बायो-बबल का कड़ा पालन करते हुए रात आठ बजे के बाद भी अभ्यास करने की अनुमति दे दी। बीसीसीआइ को जारी पत्र में आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास विभाग के सचिव श्रीरंग घोलाप ने लिखा, मैच के समय को ध्यान में रखते हुए टीमों का सीसीआइ (क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया) और एमसीए (मुंबई क्रिकेट संघ का वानखेड़े स्टेडियम) में दो सत्रों में दोपहर बाद चार बजे से शाम छह बजकर 30 मिनट और शाम सात बजकर 30 मिनट से रात 10 बजे तक अभ्यास का समय नियत किया गया है। मुंबई में आइपीएल के 10 मैचों का आयोजन होना है। ये सभी मैच वानखेड़े स्टेडियम में होंगे। इनमें से नौ मैच रात सात बजकर 30 मिनट से शुरू होंगे। वानखेड़े में पहला मैच 10 अप्रैल को चेन्नई सुपरकिंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा।

महाराष्ट्र में जारी कोरोना के कहर के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के 15 मैदानकर्मियों की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है। महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (एमसीए) के सूत्रों ने कहा कि इन लोगों को वानखेड़े स्टेडियम में बायो-बबल में शामिल किया गया है जबकि पिछले सप्ताह पॉजिटिव पाए गए दो सदस्य घर में क्वारंटाइन हो गए थे। अभ्यास सत्र बांद्रा के बीकेसी और कांदीवली के एमसीए स्टेडियम में हो रहे हैं, लेकिन आइपीएल के मुकाबले वानखेड़े स्टेडियम में होंगे।

## पीसीबी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान कई बार तोड़ा गया बायो बबल

**कराची।** पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की एक स्वतंत्र जांच समिति ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के छठे सत्र के लिए तैयार किए गए बायो-बबल (खिलाड़ियों के बचाव के लिए बनाए गए नियम) को कई मौकों पर तोड़ा गया। टूर्नामेंट के दौरान सुरक्षा के साथ समझौता किया गया। पीसीबी ने पीएसएल-6 के बायो-बबल में सेंध लगने की जांच के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया था। डॉ. सैयद फैसल महमूद और डॉ. सलमा मुहम्मद अब्बास की समिति ने पीसीबी अध्यक्ष अहसान मनी को 31 मार्च को अंतिम रिपोर्ट सौंपी। पीसीबी प्रमुख अब रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और कोई फैसला लेने से पहले बोर्ड के सदस्यों के साथ इसके विवरण को साझा करेंगे। पीएसएल को छठे सीजन को कोरोना के लगातार मामले बढ़ने की वजह से स्थगित करने पर बाध्य होना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 20 फरवरी को शुरू हुए इस टूर्नामेंट को आखिरकार खिलाड़ियों को कोरोना पॉजिटिव होने की संख्या में हो रही वृद्धि के बाद 4 मार्च को बंद कर दिया। समिति से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि रिपोर्ट में किसी व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं ठहराया गया है। रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि कराची में टूर्नामेंट के दौरान से बायो-बबल से समझौता किया गया था। इस सूत्र ने कहा कि समिति ने यह भी सिफारिश की है कि बोर्ड जून में पीएसएल-6 के फिर से शुरू होने पर किस तरह से हितधारकों के लिए सुरक्षित बायो-बबल सुनिश्चित कर सकता है ।

पीएसएल-6 को मार्च में महज 10 मैचों के बाद कोविड-19 से जुड़े मामलों के कारण स्थगित कर दिया गया था। सूत्र के मुताबिक रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने बताया कि कुछ हितधारकों ने बायो-बबल के टूटने के बारे में जानकारी दी, लेकिन पीसीबी के अधिकारियों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया।

## पोंटिंग ने की पृथ्वी की तारीफ: दिल्ली कैपिटल्स के कोच पोंटिंग ने कहा- पृथ्वी शॉ में सुपरस्टार प्लेयर बनने की क्षमता

**नई दिल्ली।** दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पोंटिंग ने कहा कि पृथ्वी शॉ में सुपरस्टार प्लेयर बनने की क्षमता है। हालांकि उसे अपने ट्रेनिंग स्टाइल में सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि शॉ ने IPLखत्म होने के बाद इस पर काम किया होगा, तभी वह विजय हजारे ट्रॉफी में वे टॉप स्कोरर रहे। इसका लाभ दिल्ली कैपिटल्स को मिलेगा। उन्होंने खुलासा किया कि शॉ पिछले सीजन में रन नहीं बनाने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते थे, उनके कहने के बावजूद भी ट्रेनिंग से इंकार कर देते थे। हालांकि जब वह मैच में रन बनाते थे, तो वह नेट्स पर जमकर बैटिंग करते थे।

पोंटिंग ने कहा, 'पिछले सीजन में पृथ्वी ने ट्रेनिंग के लिए एक अलग थ्योरी को अपनाया था। जब वह मैच में रन नहीं बना पाते थे, तो उसके बाद नेट्स पर ट्रेनिंग नहीं करते थे। वहीं जब वह रन बनाते तो वह नेट्स पर हमेशा बैटिंग करना पसंद करते थे। मैं उसके इस थ्योरी से सहमत नहीं था। उन्होंने चार-या पांच मैचों में 10 से कम रन बनाए और मैंने उनसे कहा कि उन्हें नेट्स पर बल्लेबाजी करना चाहिए, जिससे पता चले कि क्या गलती कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस करने से इंकार कर दिया। उसने गलती को सुधारने के लिए काम नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि अब उसमें बदलाव आए हैं। मुझे भरोसा है कि पिछले कुछ महीनों में इस पर उन्होंने अपनी कमियों को दूर करने के लिए काम किया और अपने प्रैक्टिस स्टाइल में परिवर्तन किया। अगर हम उनसे उनका बेस्ट ले सकें, तो वे सुपर स्टार खिलाड़ी बन सकते हैं।

# पंत आईपीएल में सचिन, द्रविड़ को पीछे छोड़ेंगे : ऋषभ रन के मामले में सहवाग-युवराज का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, विकेटकीपिंग में गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ेंगे

**मुंबई।** भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग में बतौर कप्तान खेलेंगे। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स की कमान सौंपी गई है। पंत के पास सबसे ज्यादा रन के मामले में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और जैक कैलिस के साथ वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह को भी पीछे छोड़ने का मौका है। वहीं, विकेटकीपिंग में पंत पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एडम गिलक्रिस्ट को भी पीछे छोड़ सकते हैं।

2016 सीजन से IPL में डेब्यू करने वाले पंत ने अब तक 68 मैच में 2079 रन बनाए हैं। जबकि राहुल द्रविड़ के नाम 89 मैच में 2174 और सचिन के नाम 78 मैच में 2334 रन दर्ज हैं। साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर कैलिस ने 98 मैच में 2427 रन बनाए। यह तीनों ही दिग्गज IPL से रिटायरमेंट ले चुके हैं।

**सहवाग-युवराज को भी पीछे छोड़ने का मौका**

IPL का 14वां सीजन 9 अप्रैल से 30 मई तक खेला जाएगा। पंत यदि इस सीजन में 672 रन बनाते हैं, तो वे वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह को भी पीछे छोड़ देंगे। लीग में सहवाग ने 104 मैच में 2728 और युवी ने 132 मैच में 2750 रन बनाए हैं।

2016 सीजन से आईपीएल में डेब्यू करने वाले पंत ने अब तक 68 मैच में 2079 रन बनाए हैं। जबकि राहुल द्रविड़ के नाम 89 मैच में 2174 और सचिन के नाम 78 मैच में 2334 रन दर्ज हैं। साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर कैलिस ने 98 मैच में 2427 रन बनाए। यह तीनों ही दिग्गज आईपीएल से रिटायरमेंट ले चुके हैं।

**सबसे ज्यादा रन के मामले में पंत 34वें नंबर पर:** पंत IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 34वें नंबर पर हैं। वे अब तक एक शतक और 12 अर्धशतक जड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा रन के मामले में विराट कोहली टॉप पर हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुर के कप्तान कोहली ने अब तक 192 मैच में 5878 रन बनाए हैं।

**सबसे ज्यादा शिकार के मामले में गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ेंगे पंत**

पंत के पास बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को शिकार बनाने के मामले में गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ने का मौका है। पंत इस लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं। उन्होंने अब तक 68 मैच में 54 खिलाड़ियों को शिकार बनाया। वहीं, गिलक्रिस्ट ने 80 मैच में 67 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा था। हालांकि पंत और गिलक्रिस्ट के बीच में अभी साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक भी हैं, जिन्होंने 66 मैच में 58 शिकार किए हैं। डिकॉक इस सीजन में मुंबई के लिए खेलेंगे, जबकि गिलक्रिस्ट संन्यास ले चुके हैं।

**धोनी के नाम सबसे ज्यादा शिकार का रिकॉर्ड**

विकेटकीपिंग में धोनी बेस्ट हैं। उन्होंने IPL में अब तक सबसे ज्यादा 148 खिलाड़ियों को शिकार बनाया है। दो खिलाड़ियों को पवेलियन भेजते ही वे 150 का आंकड़ा छू लेंगे और ऐसा करने वाले लीग के पहले विकेटकीपर बन जाएंगे।

**एक सीजन में हजार रन बनाने का रिकॉर्ड भी बना सकते हैं पंत**

पंत अभी शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे, टी-20) की पिछली 15 पारियों में 736 रन बनाए हैं। इस दौरान एक शतक भी लगाया है। वे 2 बार नर्वस-90 का शिकार हुए हैं। पिछले दो वनडे में उन्होंने लगातार फिफ्टी भी लगाई है। पंत के फैंस को उम्मीद है कि वे एक सीजन में हजार रन बनाने का रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। अभी एक सीजन में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम है। उन्होंने 2016 सीजन में 16 मैच खेलकर सबसे ज्यादा 973 रन बनाए थे। तब उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा 4 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया था। साथ ही 7 फिफ्टी भी जड़ी थी।